हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

10 मार्च, 2000 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 10 मार्च, 2000

	पृष्ठ संख्या
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(3)1
प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं	(3)3
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(3)3

मूल्य :

89.00

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 2000 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee met at 4.00 P.M. on Thursday, the 9th March, 2000 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and will again meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. However, the Assembly shall meet on Monday, the 13th March, 2000 at 11.00 A.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Thursday, the 16th March, 2000, Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after conclusion of the Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business from 10th March, 2000 to 16th March, 2000 be transacted by the Sabha as under :—

Friday, the 10th March, 2000 (9.30 A.M.) (First Sitting)	Discussion on Governor's Address.
Friday, the 10th March, 2000 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	Resumption of Discussion on Governor's Address.
Saturday, the 11th March, 2000	Off-day
Sunday, the 12th March, 2000	Holiday
Monday, the 13th March, 2000 (11.00 A.M.)	(1) Resumption of discussion on Governor's Address and voting on Motion of Thanks. (2) Presentation, discussion and Voting on Supplementary estimates for the year 1999-2000 (2nd instalment) and Report of the Committee on Estimates thereon.

[Mr. Speaker]

Tuesday, the 14th March, 2000 (9.30 A.M.) (First Sitting)	Presentation of Budget Estimates for the year 2000-2001.
Tuesday, the 14th March, 2000 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	Discussion on Budget Estimates for the year 2000-2001.
Wednesday, the 15th March, 2000 (9.30 A.M.) (First Sitting)	Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2000-2001.
Wednesday, the 15th March, 2000 (2.00 P.M.) (2nd Sitting)	(1) Motion under rule 30 (2) Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2000-2001 and reply by the Finance Minister. (3) Discussion and Voting on Demands for Grants for the year 2000-2001.
Thursday, the 16th March, 2000 (9.30 A.M.)	(1) Motion under rule 15. (2) Motion under rule 16. (3) The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2000-2001. (4) The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1999-2000 (2nd Instalment) (5) Legislative Business. (6) Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज जीरो आवर का तो समय होना चाहिए, क्योंकि मैंने म्यूनिसिपल कमेटीज को अबोलिश करने के बारे में अपनी कालिंग अटैंशन मोशन दे रखी है। अगर जीरो आवर नहीं होगा तो फिर मेरी इस मोशन का जवाब कहां से आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : अब तक परम्परा यही रही है कि जब प्रश्नकाल नहीं होगा तो जीरो आवर भी नहीं होता है।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे इस मोशन का जवाब कैसे आयेगा ? (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपनी एक कालिंग अटैंशन मोशन दी हुई है, उसका क्या हुआ ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आपकी मोशन आज सुबह 9.20 पर ही आई है और उसके बाद हमने उसको एग्जामिन करने के लिए भेज दिया है। जब उसका जवाब आ जायेगा तब आपको बता दिया जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी कालिंग अटैंशन मोशन है।

श्री अध्यक्ष : आपकी कालिंग अटैंशन मोशन भी अंडर कंसीडरेशन है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on the Governor's Address will take place. Shri Ram Pal Majra, M.L.A. may move his motion.

श्री रामपाल माजरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए—

"कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 9 मार्च, 2000 को सदन में देने की कृपा की है"।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी भी सरकार का आईना होता है, जिसमें सरकार की तस्वीर नजर आती है। इस अभिभाषण रूपी आईने में हरियाणा सरकार की तस्वीर खूबसूरत, मनमोहक, रचनात्मक, प्रगतिशील, पारदर्शिक एवं प्रजातांत्रिक दिखाई देती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सभी राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल हों। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की शुरूआत धर्म क्षेत्र के शपथ समारोह से हुई है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की लाईफ लाईन एस०वाई०एल० नहर है, उसे बनाने पर हमारी सरकार ने विशेष तवज्जो दी है। पहले की सरकारें आई और चली गई लेकिन उन्होंने एस०वाई०एल० नहर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे भूल गये थे कि एस०वाई०एल० नहर के बिना हरियाणा की प्यासी धरती की प्यास नहीं बुझेगी और हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती एस०वाई०एल० नहर के लिए तरसती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के समय में एस०वाई०एल० नहर के अर्थ वर्क लाईनिंग का कार्य 95% हुआ था किसानों की सरकार होने के नाते उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता एस०वाई०एल० नहर बनाने को दी थी। अध्यक्ष महोदय, जब

[श्री रामपाल माजरा]

20, फरवरी 1991 को चन्द्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब इस नहर का काम पूरा करवाने के लिए चौधरी देवी लाल जी ने इसका कंट्रैक्ट बोर्डर रोड आर्गेनाईजेशन को दिया था। उस वक्त के सबसे बड़े अधिकारी ने इस बारे में सारी जांच पड़ताल करके काम शुरू करवाना था लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से यह नहर बन नहीं सकी। अब उसी लाइन पर चलकर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने केन्द्र की सरकार से अनुरोध किया है और बार-बार मीटिंग की है कि किसानों की लाइफ-लाइन एस०वाई०एल० को जल्दी पूरा किया जाए। जैसा कि इस अभिभाषण में दर्शाया गया है कि प्रदेश की सरकार मुख्य रूप से इस बात पर केन्द्रित है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को पानी देने के लिए एस०वाई०एल० नहर का निर्माण पूरा किया जाए और इसके बनने से हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती की एक ओर जहां प्यास बुझेगी वहां किसानों की अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसानों की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो प्रदेश सुदृढ़ होगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम अति प्रशंसनीय है। सरकार की एस०वाई०एल० बनाने की जो प्राथमिकता है उससे लगता है कि प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री जो इस बात से ज्यादा चिन्तित हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। इससे पहले की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में शराब बन्दी को लागू किया और शराब बन्दी के नाम पर हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को रास्ते से भटकाया गया और प्रदेश के नौजवान रास्ता भटक गये। जिन बच्चों के बस्तों में किताब, कलम और दवात होनी चाहिए थी उनके बस्तों में काफी लम्बे समय तक शराब की बोतलें मिली और यहां तक कि कुछ राजनीतिक लोग भी इस धन्धे को करने लगे। इस आनन-फानन में शराब बन्दी हटा भी दी गई और उसका असर यह हुआ कि हरियाणा प्रदेश के नौजवान रास्ते से भटक गये और अपराध करने लग गये। कहीं पैट्रोल पम्प लूटे गये तो कहीं हत्याएं हुई और कहीं पर फिरौती वसूली में हरियाणा के नौजवान लग गये। हमारी सरकार ने इस बात को देखे बगैर कि हरियाणा प्रदेश में किस वजह से शराब बन्दी लागू की गई थी और क्यों शराब बन्दी हटा दी गई, उस वक्त में नौजवानों पर बनाये गये 48664 मुकदमें वापिस ले लिये। प्रदेश सरकार ने यह एक प्रशंसनीय काम किया है क्योंकि सरकार ने ऐसा करके उनको मुख्य धारा में शामिल करके सही रास्ते पर लाने का काम किया है। इसके अलावा जो नौजवान इस आशा में थे कि वे नौकरी लगेंगे लेकिन वे नौकरी लग नहीं पाए जिस कारण उनकी नौकरी की निर्धारित आयु सीमा खत्म हो गई। ऐसे नौजवानों के लिये हमारी सरकार ने आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष से 40 वर्ष की है। सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के लिये भलाई का काम किया है। पहली सरकारें गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देती थीं। अगर नौकरी देते भी थे तो उसके लिए पैसे का पैमाना निर्धारित था। पैमाना होने की वजह से गरीबों के बच्चे नौकरी नहीं लग पाये। आज की सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखा है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इससे नौजवानों को फिर से आशा बन्धी है। इसलिये नौकरियों में आयु सीमा 35 से 40 वर्ष करने का सरकार का यह एक सराहनीय काम है। पहले के मुख्य मंत्री यह कहा करते थे कि बुढ़ापा पैन्शन हो ही नहीं सकती, अगर हो सकती तो मैं कर देता। उस समय चौधरी देवी लाल जी कहा करते थे कि बुढ़े मर न जाना मैं तेरी पैंशन कर दूंगा। चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की कलमदान संभालते ही हरियाणा प्रदेश के बूढ़ों की पैंशन शुरू कर दी। उनकी सरकार के पश्चात् फिर जो सरकार आई तो उस सरकार ने उस पैंशन को काटना शुरू कर दिया था। कहीं पर जमीन की पाबन्दी लगा दी तो कहीं पर यह पाबन्दी लगा दी कि उसका एक लड़का नौकरी में था। उन सरकारों ने पैंशन काटने का काम किया न कि नई पैंशन बनाने का। इस अभिभाषण में विशेष तौर से दर्शाया है कि अब ऐसी कंडीशन्ज हटा दी गई हैं। पांच एकड़ भूमि की कंडीशन को हटा दिया गया है और किसी का लड़का नौकरी करता है तो उस कंडीशन को भी हटा दिया गया है और नये सिरे

से सर्वे कराकर उन पात्रों को पैंशन के लिये शामिल किया गया है जो काफी समय से वंचित कर दिये गये थे। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं। हमारी सरकार ने पैंशन भी दुगुनी करके 100/- रुपये से 200/-- रुपये प्रति माह कर दी है। मुख्य मंत्री जी ने यह एक सामाजिक संरचना का कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों पर पहले की सरकार ने झूठे मुकद्दमे बनवाये थे। उनकी सरकारों में निर्सिंग, कादमा, टोहाना, मंडियाली, नारनौंद, कोलेखां इगरा व मण्डियाली आदि में न जाने कितनी जगहों पर हरियाणा के अन्दर किसानों पर गोलियां चलाई गई थीं। उन सरकारों के दौरान किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। इस सरकार ने आते ही सर्वप्रथम किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए जो झूठे मुकद्दमे किसानों पर पहले की सरकारों के समय में बनाए गए थे, वे वापस ले लिए ताकि कोई किसान बेवजह परेशान न हो। इसी प्रकार से सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए खाद के रेट प्रति कट्टे 5 से 10 रुपये कम किए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। सरकार ने थोड़े समय में ही किसानों को सुविधा देते हुए हरियाणा प्रदेश के लिए दो नई चीनी मिलें लगाने का फैसला लिया। सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए ही ऐसा निर्णय लिया क्योंकि किसान के लिए गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है। जिसमें दूसरी फसलों की अपेक्षा कम बीमारी लगती है। गन्ने की फसल अधिक वर्षा हो या सूखा पड़ जाये तो उसको भी सहन कर लेती है। गन्ने की फसल किसान को कम घाटा पहुंचाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो नई चीनी मिलें लगाने का फैसला लिया है। इसी के साथ-साथ सरकार ने हैफेड के तहत कैटल फीड प्लांट भी लगाने का फैसला लिया है। हमारे सदन के सभी साथियों को पता है कि पीछे बाढ़ अधिक आने के कारण हमारे किसान भाईयों की 5-5 फसलें नहीं हो पाई थीं। मौजूदा सरकार ने बाढ़ की समस्या की तरफ विशेषतौर से ध्यान दिया है और इस बारे में बड़ी चिन्तित भी है इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि मानसून आने से पहले पहले हमारे प्रदेश की जितनी भी नहरें, ड्रेनें व रजवाहे आदि हैं उन सभी की सफाई सरकार करवाएगी ताकि हमारा प्रदेश बाढ़ रहित प्रदेश हो सके। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने एक और अहम् कार्य किया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को अच्छी तरह से समझा और जाना है। पहले जब कोई बहन अपने भाई के नाम कोई जमीन ट्रांसफर करवाती थी तो उस पर 14-15 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लग जाती थी जिस कारण तकरीबन एक एकड़ जमीन तो ऐसे ही सरकारी खाते में चली जाती थी जिसका नुकसान उसके भाई को होता था। सरकार ने इस ब्लंड रिलेशन को समझते हुए जो जमीन की ट्रांसफर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी उसको समाप्त कर दिया है। यह इस सरकार का अति सराहनीय कदम है और सरकार वाकई इस काम के लिए बधाई की पात्र है। सरकार किस के लिए होती है ? सरकार होती है Government of the people, by the people, for the people. लेकिन पिछली सरकारों ने इसके मतलब को न समझते हुए क्या कर दिया ? उन्होंने कर दिया Government off the people, buy the people, far the people. विशेषतौर पर इस सरकार ने एक और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। यह सराहनीय कार्य सरकार आपके द्वार तक पहुंच कर किया। पहले लोगों का कोई डैपूटेशन जब मुख्य मंत्री जी से या मंत्रियों से मिलने आता था तो लोग यहां पर धर्मशालाओं में और होटलों में 2-3 दिन तक ठहर कर चले जाते थे लेकिन उनका मुख्य मंत्री जी से और कई बार मंत्रियों से सम्पर्क नहीं हो पाता था जिस वजह से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। सरकार ने इस बात को समझते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जिसके जरिये लोगों का समय और पैसा भी बचा। इतना ही नहीं मुख्य मंत्री जी ने मौके पर फैसले लिए। मौके पर ही मुख्य मंत्री जी ने गांवों वालों से पूछा कि बताओ आपकी समस्या क्या है ? लोगों ने

[श्री रामपाल माजरा]

जो समस्याएं बताईं उनका निदान भी उसी समय करने की कोशिश की। जहां पर स्कूल अपग्रेड करने थे, मौके पर ही आदेश दिए गए। कहने का मतलब यह है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज गांवों-गांवों में हरिजन चौपालें बनाने का काम, स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम या जो भी अन्य काम उस संबंधित गांव से थे, सभी पर कार्य चल रहा है। इस प्रकार के जो कार्य मौजूदा सरकार ने किए वे कोठी में बैठकर नहीं किए जाते बल्कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझते हुए किए जाते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिस पर सरकार ने चलाया है उस बारे में मेरा सभी माननीय साथियों से निवेदन है कि वे भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलाएं ताकि लोगों की समस्याओं का निपटान शीघ्र हो सके। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हम सबके लिए एक सबक है।

पहली सरकारों के समय में जब सदन में बहस चलती थी तो यहां पर बैठकर विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हम देखा करते थे कि प्रोफैसर सम्पत सिंह जी जब विधान सभा में कागज लहरा कर कुछ कहने की कोशिश किया करते थे तो उनकी बात को सुना नहीं जाता था, उनको वह कागज पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समय हम सोचा करते थे कि पता नहीं क्या बात है जो कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मैडिकल कॉलेज अग्रोहा की ग्रान्ट बन्द कर दी गई थी तो जब यह मामला यहां पर हाउस में उठाया जाता तो मुख्य मन्त्री कहते थे कि मैंने ग्रान्ट बन्द नहीं की दूसरे पूर्व मुख्य मन्त्री ने बन्द की है। जब दूसरे मुख्य मन्त्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह ग्रान्ट मैंने बन्द नहीं की वह तो दूसरे मुख्य मन्त्री ने बन्द की थी। अध्यक्ष महोदय, वे लोग एक-दूसरे का नाम ले लेते थे परन्तु वर्तमान सरकार के मुखिया ने इस बात को जानने की कोई कोशिश नहीं की कि यह ग्रान्ट किस ने बन्द की, उन्होंने इस बात की गहराई में जाने की कोई कोशिश नहीं कि यह ग्रान्ट किसने और क्यों बन्द की। वहां की परेशानी को देखते हुए वर्तमान सरकार के मुखिया ने सरकार बनते ही अढ़ाई घण्टे में ही मैडिकल कॉलेज, अग्रोहा को सात करोड़ रुपये की ग्रान्ट जारी कर दी और वह कॉलेज जो कि बन्द पड़ा था उसका ताला खोलने का काम और कॉलेज को दोबारा चालू करने का काम इस सरकार के मुखिया ने ही किया। वे लोग जो कि कहते थे कि यह सरकार केवल किसानों की सरकार है, उनका यह भ्रम भी सरकार ने दूर कर दिया है। टैक्सों का सरलीकरण करके चाहे वह फार्म 14-ए या 15-ए फार्म की बात हो, चाहे चुंगी समाप्त करने की बात हो वह काम भी इस सरकार ने किया है। चुंगी की प्रथा 20 साल पुरानी प्रथा थी अब उस प्रथा को समाप्त किया गया है। इसके अलावा इस सरकार ने अनेकों क्षेत्रों में नये आयाम स्थापित किए हैं। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की समस्याओं को भी हल किया गया है। जब म्यूनिसिपल कमेटीज़ के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी तो उस वक्त छोटे-छोटे कर्मचारियों को जेलों में डाल दिया गया था। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की उस समय की सरकार ने नादिरशाही दिखा कर उन कर्मचारियों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया था। म्यूनिसिपल कमेटियों के कर्मचारियों तथा सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ झूठे मुकद्दमें बना कर उन्हें नौकरियों से वंचित कर दिया था। वर्तमान सरकार के मुखिया ने परमानैंट कर्मचारियों को नौकरियों पर बहाल किया और उनके खिलाफ जो झूठे मुकद्दमें बनाए गए थे उनको वापिस लिया और एक नई प्रथा कायम की। इस सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मैडिकल कॉलेज, अग्रोहा की ग्रान्ट बहाल की, टैक्सों का सरलीकरण किया, चुंगी समाप्त की और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करके जो नये आयाम स्थापित किए हैं मैं उनके लिए इस सरकार को बधाई देता हूं। विधवाओं की पैंशन 100/--रुपये से बढ़ा कर 200/- रुपये प्रति माह करके उनको सम्मान दिया गया है। इसी प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने जच्चा-बच्चा के लिए अजवायन और पंजीरी के लिए 500/- तथा 300/- रुपये की राशि गरीब हरीजन माता को दे कर उन्हें सामाजिक

संरक्षण प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जी रहे हैं उनके लिए हरिजन कन्याओं की शादी के लिए 5100/- रुपये कन्यादान के रूप में दे कर एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और सारे देश के अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के फैसले लेने के बारे में विचार चल रहा है और वे प्रदेश हरियाणा का अनुकरण कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शहीदों की शहादत की राशि कभी एक से दो लाख होती थी और वह राशि दो से तीन लाख करवाई। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विपक्ष के नेता थे तो यह राशि पांच लाख रुपये करवाई थी लेकिन जब वे स्वयं हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने तो इस पांच लाख की राशि को बढ़ा कर दस लाख रुपये कर दिया गया। ऐसे शहीदों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की राशि का अनुदान दे कर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा के किसान जब भी गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए मांग करते थे तो उन्हें कोई एजिटेशन वगैरह करना पड़ता था। उस एजिटेशन में उन पर लाठियां चलवाई जाती थीं व ठण्डे पानी के फव्वारे बरसाए जाते थे। उसके बाद भी जो रेट बढ़ाया जाता था वह 50 पैसे या एक रुपया बढ़ाया जाता था। हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने गन्ने का रेट 100 रुपए प्रति क्विंटल किया है जो कि बहुत ही सराहनीय है। मजदूरों की मजदूरी के लिए भी इस सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं। व्यापारियों और कृषकों के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं और करते चले आ रहे हैं। मैं तो आप सब मित्रों से यही कहूंगा कि आप सब इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। हरियाणा प्रदेश में सूखे की समस्या थी लेकिन इस सरकार ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाई। केन्द्र पूल से 19 प्रतिशत से 27 प्रतिशत बिजली लेने का काम भी इस सरकार ने किया। मैं तो यह कहूंगा कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण इस नई सदी में नए हरियाणा के नव निर्माण में नया संदेश है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहूंगा कि यह तो अभी ट्रेलर है पूरी फिल्म तो बजट में देखने को मिलेगी। यह कह कर मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वे सब इस प्रस्ताव का समर्थन करें। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, Shri Krishan Pal will second the motion.

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के एड्रैस पर जो प्रस्ताव भाई राम पाल माजरा जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बारे में अपनी कोई बात कहूं उससे पहले मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और चुनाव में लगे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चौधरी साहब के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया कुशलता पूर्वक सम्पन्न हुई। देश में जहां चुनावों में दंगे होने की बात सुनी जा रही थी वहीं हमारे यहां पर चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हरियाणा की जनता भी बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय 24 जुलाई 1999 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनी थी। यह पहली बार हरियाणा में हुआ है कि किसी सरकार के रहते हुए जनता ने उसी सरकार में अपना विश्वास जताया है। उसके पक्ष में वोटिंग हुई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने व्यापारियों, किसानों, उद्योगों और मजदूरों के प्रति जो अच्छे निर्णय लिए थे आज यह सब उसी का परिणाम है। उन सब निर्णयों को देखते हुए हरियाणा की जनता ने सरकार की बागडोर फिर से इनके हाथों में सौंप दी है। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूं।

[श्री कृष्ण पाल]

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के जो किसान गन्ना पैदा करते हैं जब वे गन्ने की अच्छी कीमत मांगते थे तो धरना देते या एजिटेशन करते थे तो उनको लाठियों से मारा जाता था लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 110 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दिया है। इसके अलावा 10 रुपए प्रति बोरी यूरिया की और डी०ए०पी० की बोरी पर 5 रुपए का प्रोत्साहन दिया है उसके लिए भी मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सरकार ने वृद्धावस्था पैंशन डबल की है, विकलांगों की पैंशन भी डबल की है। अनुसूचित जाति की कन्याओं की शादी पर 5100/- रुपए देने की जो घोषणा 10.00 बजे की है इससे जनता में एक अच्छा संदेश जाता है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, चाहे सड़कों की मरम्मत करने की बात हो, चाहे नालियां बनाने की बात हो, चाहे पशु औषधालय बनाने की बात हो या चाहे औषधालय बनाने की बात हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। जब मुख्य मंत्री जी जगह-जगह पर जनता दरबार लगाते थे तो उस समय विपक्षी कहते थे कि उनके द्वारा की गयी सारी घोषणाएं झूठी हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां-जहां पर भी उनके द्वारा ये दरबार लगाये गये वहां-वहां पर एक हफ्ते के अंदर पैसों के ड्राफ्ट बनकर चले गये और उसके कुछ ही दिनों बाद वहां काम शुरू हो गये और उसी का यह परिणाम है कि हरियाणा की जनता ने आज उनको सत्ता की बागडोर सौंपी है। अध्यक्ष महोदय, सूखे की वजह से जो बिजली में कमी आयी थी उसको सरकार ने केन्द्र सरकार से कहकर बढ़वाया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक चुंगी समाप्ति की बात है हम उस समय बार-बार कहते थे कि चुंगी समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि यह बात हमारे घोषणा पत्र में भी है लेकिन उस समय हमारी बात नहीं सुनी गयी। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने शपथ लेने के बाद तुरन्त ही चुंगी समाप्ति की घोषणा कर दी जिससे हरियाणा के व्यापारियों को एवं उद्योगपतियों को राहत मिली इसलिए इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। सरकार के इस कदम से जो कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे उनको भी सरकार ने दूसरे डिपार्टमैंट्स में समायोजित किया है जिसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जो मार्किट फीस पहले दो प्रतिशत कर दी गयी थी उसको चौटाला साहब ने एक प्रतिशत किया इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह से दो प्रतिशत ग्रामीण विकास उपकर की समाप्ति के लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पहले मंडियों में खुली बोली द्वारा आढ़तियों को प्लाटों की नीलामी की जाती थी लेकिन अब इस सरकार ने इन आढ़तियों की भावनाओं को समझते हुए यह नीति बदल दी है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सरकार की बदली हुई नीति से अब आढ़तियों को और व्यापारियों को राहत मिलेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब यह बात नहीं कह सकते क्योंकि उस समय इन्हीं की सरकार ने यह फैसला किया था। ये भी तो उस समय उस सरकार में शामिल थे। अगर चौटाला साहब यह बात कहें तब तो मानी जा सकती है।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, अगर उस समय हमारी बात मान ली गयी होती तो हम सरकार से बाहर ही नहीं आते। जब हमारी बात नहीं मानी गयी तो उसके बाद ही हम सरकार से बाहर आ गये। बाद में चौटाला साहब ने हमारी बात मान ली इसलिए आज हम उनको समर्थन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार द्वारा बिक्रीकर नियमों का सरलीकरण करना भी एक अच्छा कदम है इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। व्यापारियों को और दुकानदारों के लिए स्वयं कर निर्धारण स्कीम को लागू करना भी एक अच्छा कदम है। इसी तरह से सरकार द्वारा नयी औद्योगिक नीति का आरंभ करना एवं किसानों और कर्मचारियों के विरुद्ध बनाये गये केसिज को

वापस लेना भी एक बहुत ही अच्छा कदम है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम अग्रोहा मैडीकल कालेज की ग्रांट बहाल करने की मांग समय-समय पर करते रहे लेकिन हमारी बात नहीं मानी गयी। यह ग्रांट भजन लाल जी ने बंद की थी और बंसी लाल जी ने भी उसको ऐसे ही रखा लेकिन चौटाला साहब ने उसको बहाल करके एक अच्छा काम किया है मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह से अध्यापकों के लिए राज्य स्तरीय पुरूस्कार को दुगना करना भी एक अच्छा कदम है। मैं सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए बधाई देना चाहता हूं।इसी तरह से कारगिल के शहीदों को दी जाने वाली राशि को दुगना करना भी सरकार का एक सराहनीय कदम है मैं इसके लिए भी इनको बधाई देना चाहता हूं। पिछली सरकार ने पहले तो यह राशि बहुत कहने पर दो लाख रूपये की थी लेकिन जब हमने इस बारे में बार-बार कहा तब जाकर यह राशि पांच लाख रूपये की गयी थी लेकिन चौटाला साहब ने इस राशि को दुगना कर दिया। जिससे शहीदों के लिए सम्मान पैदा हुआ उसके लिए मैं श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जो जख्मी सैनिक थे उनके लिए सहायता राशि 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी उसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। नशाबंदी के दौरान जो लोगों के खिलाफ और विशेषकर युवकों के खिलाफ केस बनाए गए थे उनमें से 48664 मामलों को वापस लेना एक नया सन्देश है और उसके लिए भी मैं श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकारी नौकरियों में प्रवेश की आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई उससे बेरोजगार युवकों को लाभ होगा उसके लिए भी मैं चौटाला जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए भी नये-नये कदम उठाए गए। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए। नयी औद्योगिक नीति नवम्बर से शुरू की गई ताकि नये निवेश प्राप्त हो सकें। निरीक्षकों के दौरे कम किए गए और चुंगी की समाप्ति से वाणिज्य व व्यापार के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त कर दिया गया लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इससे शहरी क्षेत्रों में विकास के काम में रुकावट आई है, मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शहरों का चहुमखी विकास हो सके इसके लिए अलग से राशि का प्रबन्ध करें ताकि शहरों का विकास सुचारू रूप से हो सके। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को विकसित करने के लिए औद्योगिक विकास निगम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्यमियों को आवंटित करने हेतु 4 हजार एकड़ विकसित भूमि का भूमि बैंक बनाने का प्रस्ताव है इसके लिए श्री चौटाला जी की सरकार बधाई की पात्र है। हरियाणा वित्त निगम ने बुनकरों और शिल्पियों के उत्पादन की समुचित बिक्री व्यवस्था करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि बिजली के लिए पिछले 15 साल से हरियाणा का किसान, व्यापारी व उद्योगपति चिंतित था और किसी भी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बिजली का सुनिश्चित और सुचारू होना बहुत जरूरी है। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेकों कार्य किए गए। पानीपत के 110 मेगावाट के 4 बिजलीघरों को अपग्रेड किया गया और उनके पॉवर फैक्टर लोड को भी बढ़ाया गया। पानीपत की छठी यूनिट को शुरू किया गया। फरीदाबाद में 420 मेगावाट का गैस बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट है उसे चालू किया गया है उसकी दो यूनिट 143 मेगावाट की चालू की गई हैं तीसरी 46 मेगावाट की यूनिट के जून 2000 तक शुरू होने की संभावना है। जब सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी, फसल के नष्ट होने की संभावना पैदा हो गई थी तो उस वक्त इन्होंने सैन्ट्रल गवर्नमैंट से निवेदन कर के 27 फीसदी बिजली को बढ़वाया इससे दस लाख यूनिट बिजली की बढ़ौतरी प्रतिदिन हुई है उसी के कारण जहां 25 सितंबर 1999 को 518.40 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई हुई है वहीं उससे गत वर्ष उसी समय 458.05 लाख यूनिट बिजली की

[श्री कृष्ण पाल]

सप्लाई हुई थी। इसके अतिरिक्त भी अनेक सब-स्टेशन लगाए गए, कुछ को अपग्रेड किया गया इससे रबी की फसल अच्छी हुई और शीतकालीन वर्षा के कम होने के बावजूद भी रबी की फसल को बचाना संभव हो सका। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के आंटा गैस स्टेशन से हिस्सा बढ़वाया गया। इन दोनों कार्यों के परिणामस्वरूप हमारी उपलब्धता 10 लाख यूनिट प्रतिदिन बढ़ रही है। 110 मेगावाट वाला थर्मल प्लांट 112 में अपग्रेड हुआ है इस प्रकार हरियाणा में बिजली की पैदावार बढ़ी है इसके लिए चौटाला साहब बधाई के पात्र हैं। यह सरकार बिजली की ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है ताकि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चालू वित्त वर्ष में 13 नए ग्रिड सब स्टेशन शुरू किए गए हैं। 97 सब स्टेशन की क्षमता में वृद्धि की गई है। 264 किलोमीटर लम्बी उच्च वोल्टेज की लाइनें बिछाई गई हैं जिससे यमुनानगर, शाहबाद, पेहवा, अम्बाला और पंचकूला के आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व वोल्टेज में काफी सुधार हुआ है। 5950 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं तथा पुरानी तारों को बदला जा रहा है जिससे बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई प्रणाली को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए गये। अनेक माईनरों को बनाया गया, रजबाहों को बनाया गया, मानसून आने से पहले नहरों की सफाई की गई जिसके कारण सिंचाई के क्षेत्र में सिंचित मात्रा को बढ़ाया गया है तथा किसानों के खेतों की अंतिम टेल तक पानी पहुंचाया गया है इसके लिए मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहता हूं।

शहरों के विकास के लिए भी अनेक कार्य किए गये हैं। हरियाणा शहरी प्राधिकरण द्वारा अनेक शहरों में नगर पार्क बनाये गये हैं तथा शहरी सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। यहां विद्यालय, डिस्पैंसरियां, क्लब, सामुदायिक केन्द्र तथा पुलिस थाने बनाकर सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके लिए भी मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहता हूं। फरीदाबाद में जहां गरीब तबके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से जो ग्रान्ट आती थी पिछली सरकार ने उसे बन्द कर दिया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस ग्रान्ट को पुनः बहाल किया जाये। फरीदाबाद में जहां अनाधिकृत कालोनियाँ हैं उनमें 29 प्रतिशत बिजली के मीटर नहीं लगे हुए हैं परन्तु बिजली की सप्लाई वहां पर फिर भी चालू है इससे सरकारी रैवन्यू का काफी नुकसान हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इन कालोनियों में बिजली के मीटर लगवायें ताकि सरकारी पैसे का नुक्सान न हो। ऐसा तभी संभव होगा जब वे इन कालोनियों को रैगुलराइज करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में भी अनेक महत्पूर्ण कार्य किए गये हैं। 1999-2000 के लिये खाद्यान्नों के उत्पाद का लक्ष्य 122.50 लाख टन रखा गया है, जिसमें 37 लाख टन खरीफ के लिये और 85.50 लाख टन रबी की फसल के लिये है। इसी प्रकार गन्ने, कपास और तिलहन का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः गुड़ के रूप में 9 लाख टन, 12 लाख गांठे कपास के लिए और 10.20 लाख टन तिलहन के लिए रखा गया है। पिछले वर्ष 1999 के दौरान अत्यधिक कम वर्षा होने के कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राज्य में 1999 के दौरान खरीफ का उत्पादन 30.70 लाख टन हुआ जबकि 1998 के दौरान 31.54 लाख टन उत्पादन हुआ था जिससे इस वर्ष थोड़ा सा कम हुआ है। चालू वर्ष के दौरान तिलहन का उत्पादन लगभग 7.19 लाख टन होने की आशा है जबकि गत वर्ष 6.42 लाख

टन उत्पादन हुआ था। गन्ने का उत्पादन 8 लाख टन होने की आशा है जबकि गत वर्ष के दौरान 6.88 लाख टन उत्पादन हुआ था। कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के उत्पादन की नियमित बिक्री के लिए उन्नत तथा सुलभ बाजार सुविधायें जुटाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसके लिए वह बधाई का पात्र है। वर्ष 1969 में बोर्ड के गठन के समय राज्य में केवल 58 मुख्य यार्ड और 60 उप-यार्ड थे। इस समय, बोर्ड के पास समूचे राज्य में फैले 105 मुख्य यार्ड 178 उप-यार्ड और 142 खरीद केन्द्र हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान मार्किट शुल्क के रूप में वसूल किये गये 100 करोड़ रूपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के लिये 120 करोड़ रूपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को गड्ढा रहित बना दिया गया है। बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए 12.5 करोड़ रूपये की लागत से उचानी करनाल में एक बागवानी प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। गांवों की गलियों को पक्का करवाना, गांवों में नालियों को पक्का करवाना, मैचिंग ग्रांट स्कीमों को डबल करना, गांवों के विकास के लिए सरकारी स्कूलों के कमरों को बनवाना आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसलिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वन के क्षेत्र में जहां भौगोलिक क्षेत्र का केवल 3.38 प्रतिशत क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र है। वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान 39,390 हैक्टेयर पंचायत भूमि पर अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमि की बुवाई परियोजना के अधीन वनरोपण किया जा चुका है जिससे दूषित पर्यावरण को रोकने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने पिछले 7 महीने में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनको देखकर ही हरियाणा की जनता ने इन्हें वोट दिए और हरियाणा की सत्ता इनको सौंपी। इसके अलावा मैं इन सबको बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों से साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया लेकिन मुख्य मंत्री महोदय अभी भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। यह विधान सभा की बैठक है, न कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है। (शोर)

Motion moved—

'That an address be presented to the Governor in the following terms—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 9th March, 2000."

सदस्यगण, प्रत्येक मैम्बर के हिस्से में करीब 10 मिनट का समय आता है इसलिए सभी मैम्बर समय सीमा में रहकर अपनी बात को समाप्त करें। सभी मैम्बर्ज ने अपनी बात कहनी है इसलिए सभी को बराबर समय दिया जाएगा।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में शानदार अभिभाषण दिया। इन्होंने बहुत ही सुन्दर शब्दों में इसकी व्यवस्था की। सरकार जो भाषण

[श्री भजन लाल]

उनको बनाकर देगी वह तो उनको पड़ना ही पड़ेगा। (शोर) अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार बनी हुई हमारे सामने बैठी है, इस सरकार को अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसको बने हुए अभी चार दिन ही हुए हैं। 4 दिन के अन्दर हम इनको क्या कह सकते हैं ? लेकिन पिछले 7 महीनों में जब से श्री ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्य मंत्री बने हैं उसके बारे में कहूंगा कि किसी ने इनके सामने अपनी 10 मांगें रखी तो इन्होंने राज लेने के लिए उनकी 20 मांगें पूरी करने का वायदा किया ताकि किसी तरह राज इनके हाथों में आ जाए। इन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी कि अगर 30 साल तक भी ये मुख्य मंत्री बने रहे तो भी ये घोषणाएं पूरी होनी मुश्किल हैं। (शोर) मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है केवल असलियत ही बताई है, क्योंकि बंसी लाल ने बहुत से ऐसे काम कर रखे थे जिनको ठीक करने में समय तो लगना ही था। बहुत से ऐसे झमेले हैं जिनका मैं आगे चलकर जिक्र करूंगा। कल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एस०वाई०एल० का जिक्र किया। उन्होंने एस०वाई०एल० का जिक्र तो कर दिया और सारी सरकारें इसका जिक्र करती रही हैं परन्तु काम किसी ने नहीं किया। मैं अपने मुंह से तारीफ करता अच्छा नहीं लगता कि हमारी सरकार के समय में ही एस०वाई०एल० कैनाल के पानी का फैसला हुआ। भजन लाल ने ही श्रीमती इन्दिरा गांधी जो आज इस संसार में नहीं हैं, से एस०वाई०एल० कैनाल की आधारशिला रखवाई और काम शुरू हुआ था। यह रिकार्ड की बात है। (शोर) एस०वाई०एल० का 90 प्रतिशत काम हमारी सरकार के समय में ही हुआ। यह रिकार्ड की ही बात है। बाद में पंजाब में उग्रवाद के मामले में तेजी आ गई। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं पिछली बातें नहीं करूंगा और अभी कहने को इतना कुछ है नहीं। अगर यह सरकार अच्छे काम करेगी तो हम इसकी तारीफ करेंगे और अगर वे गलत काम करेंगे तो हम इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एस०वाई०एल० नहर के बारे में कहना चाहूंगा जो हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। एस०वाई०एल० नहर का पानी अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की जनता को दिलवा देंगे तो हम इन्हें देवता मान लेंगे। चौधरी बंसी लाल जी ने यहीं हाऊस के अंदर कहा था कि वे हरियाणा के अन्दर गंगा का पानी लेकर आयेंगे तब मैंने चौधरी बंसी लाल जी से कहा था कि अगर आप गंगा का पानी हरियाणा में ले आयेंगे तो मैं अपने हाथ से आपके पैर धोकर पी लूंगा। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अन्दर बादल साहब मुख्य मंत्री हैं और हमारे यहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्य मंत्री हैं, चौधरी देबी लाल जी हैं। इनका बादल साहब के साथ एक परिवार का रिश्ता है। (विघ्न)

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी भी तो अपनी अचीवमैंट्स के बारे में बतायें। जब इनकी सरकार थी उस वक्त इनकी सरकार ने क्या किया ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी गोपी चन्द जी पहली बार विधान सभा में आये हैं। इनको क्या मालूम हमने क्या-क्या कार्य किये हैं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोपी चन्द जी, प्लीज आप बैठिये।

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी जो बात कर रहे हैं उस बारे में हम इनसे भी तो पूछ ही सकते हैं कि इन्होंने अपनी सरकार के वक्त में इस बारे क्या किया ? (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : गोपी चन्द जी, प्लीज आप बैठिये। जय प्रकाश जी, प्लीज आप भी बैठिये। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बार कई नये सदस्य चुनकर आये हैं। लेकिन वे अब तक जैसा गांव में माहौल देखा करते थे वैसा ही यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता अपने इन नये साथियों को बता दें कि यह विधान सभा है और इसके डैकोरम को कायम रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। कोई भी सम्मानित सदस्य, सम्मानित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह यहां हाऊस में पहुंच गया है। इसलिए हम सब सम्मानित सदस्य हैं और हमें अध्यक्ष की अनुमति के बगैर बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बोलना है तो अध्यक्ष से अनुमति लेकर ही बोलें। अगर अपने आप ही खड़े होकर बोलेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो लोग सदन की दर्शक गैलरी में बैठे हैं वे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आप यहां आकर सुधर जायेंगे लेकिन अब वे भी आपका व्यवहार यहां देखकर ऐसा सोचते होंगे कि हमसे गलती हुई है। इसलिए आप अध्यक्ष से परमिशन लेकर ही बोलें।

डा० जय प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो बात लीडर आफ दी हाऊस ने कही है यह बात आप कह सकते थे, ये नहीं कह सकते थे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो बात सभी पार्टियों के नेताओं से कही है, उस पर सभी नेता चिंतन करें और किसी भी सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ होती हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि 31 नये सदस्य इनकी पार्टी के हैं और 8 नये सदस्य हमारी पार्टी के हैं। ये अपने 31 सदस्यों को काबू में रखें, मैं तो अपने 8 को रख लूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि एस०वाई०एल० नहर जो हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। इसका पानी हरियाणा में हर हाल में आना चाहिए। हम इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। जहां कहीं भी हमारी जरूरत हो, हमारे विधायकों की जरूरत हो, एजीटेशन करने की जरूरत हो, कहीं चलने की जरूरत हो तो हम बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम इनका पूरा साथ देंगे और इनकी मेहरबानी होगी अगर ये एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा को लाकर देंगे। हरियाणा के लोगों को बड़ी परेशानी है और आधी से ज्यादा धरती सूखी पड़ी है, पीने का पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब बिजली की बात आती है, पूर्व मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल जी 24 घण्टे बिजली देने का नारा दिया करते थे और कहा करते थे कि हम हरियाणा को 24 घण्टे बिजली देंगे लेकिन समझ नहीं आता कि ये चार घण्टे को 24 घण्टे कहते हैं या फिर 24 घण्टे को 4 घण्टे कहते हैं। हरियाणा प्रदेश को पूरे 4 घण्टे भी बिजली नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आने से पहले ये भी कहते थे कि हम बिजली, पानी मुफ्त देंगे। अब पता नहीं कि ये ऐसा करने वाले हैं या नहीं। अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया है। बिजली के उदारीकरण के लिये वर्ल्ड बैंक ने जो लोन सैंक्शन किया था, कहते हैं कि वह लोन भी कैन्सल कर दिया गया है और वर्ल्ड बैंक हरियाणा को लोन नहीं देगा। सरकार को गुडविल के आधार पर ही वर्ल्ड बैंक या बिजनैस मैन लोन देते हैं। सरकार की गुडविल पर पूरा भरोसा ही कि वह स्कीम के आधार पर ठीक काम करेगी तभी लोन मिलता है। अगर गुडविल न हो तो कोई लोन नहीं देता।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : पंवार जी, कहिये, आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है ?

श्री कृष्ण लाल : सर, जैसा कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री भजन लाल बिजली के सम्बन्ध में बोल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि (शोर एवं व्यवधान) 1993 के अन्दर इन्होंने एक

[श्री कृष्ण लाल]

अमरीकन कम्पनी जो कि नीरा कम्पनी के नाम से है उसको बिजली के प्राइवेटाइजेशन के लिये ढाई करोड़ रूपये दिये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनके ज्यादा पुराने सदस्य भी बीच-बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं जो कि ठीक नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदस्य ने तो इनकी पुरानी बात याद कराई है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात को तो सरकार ही देखे कि हमारी बात ठीक थी या नहीं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था बिजली और पानी के बारे में। फिर किसानों की बात आती है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। गवर्नर एड्रैस में एक पैरा तो किसानों के बारे में डाला है लेकिन क्या-क्या योजना है और किस योजना पर कितना पैसा खर्च करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामीण विकास योजना पर चर्चा तो डाल दी लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि देहातों में रहने वाले किसान भाईयों, हरिजन भाईयों, बाल्मिकी भाईयों और छोटे दुकानदार भाईयों के लिये क्या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है जो कि होना चाहिए था। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 29 नगरपालिकाओं को भंग कर दिया है जबकि पंचायतों के चुनाव चालू हैं। इसलिये इन नगरपालिकाओं को भी फिर चालू किया जाए, जो कि जरूरी है क्योंकि लोगों में बड़ा भारी रोष है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे प्रोजैक्टस भी थे जिन पर पहले से काम चल रहा था। अब इन प्रोजैक्टस का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड जो बना हुआ था उसका इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया। इसी प्रकार से शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड जो बनाया गया था उसका भी इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड इसलिए बनाया गया था ताकि इस पहाड़ी एरिया को उन्नत किया जा सके और इसे सुन्दर बनाया जा सके। ऐसे कुछ और भी प्रोजैक्टस हैं जिनका इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। स्पीकर साहब, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी अभी यह नई सरकार बनी है। आने वाले समय में सरकार के कार्य देखेंगे। इसके बाद जो छः महीने बाद सैशन होगा उसमें खुलकर विचार रखेंगे ताकि तब तक सरकार को भी अपना कार्य करने का मौका मिल सके। अब मैं ज्यादा न बोलते हुए निवेदन करता हूं कि मेरा समय भी आप हमारे जो नए विधायक आए हैं, उनको दे दिया जाये ताकि वे भी अपने विचार खुलकर सदन में रख सकें। धन्यवाद।

श्रीमती अनीता (साल्हावास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सरकार के नोटिस में कुछ मुद्दे लाना चाहूंगी जिन पर सरकार को उचित ध्यान देकर काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहती हूं कि सरकार ने जो एक स्कीम हरिजन की लड़कियों की शादी के लिए बनाई हुई है कि किसी हरिजन लड़की की शादी होगी तो सरकार की तरफ से उसको 5100 रूपये दिए जाएंगे। इस बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि एक एक गांव में एक दिन में तीन तीन हरिजन लड़कियों की शादियां हुई हैं लेकिन किसी को कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिला। इस बारे में हम अधिकारियों के पास चक्कर लगाते रहे लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी जिस वजह से उन गरीब हरिजन भाईयों की कोई मदद

नहीं हो पाई। सरकार जो कह रही है कि हम हरिजनों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सरासर गलत है। हमारे एक माननीय साथी ने जो यह कहा कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा उस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह प्रोग्राम 100 प्रतिशत फेल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे एरिया में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। कभी-कभार कोई एस०डी०एम० या डी०एस०पी० किसी गांव में पहुंचा भी तो वह भी चाय आदि पीकर वापस आ गया लेकिन उन्होंने भी लोगों की समस्याओं को निपटाने में कोई कार्य नहीं किया। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगी कि लोगों के छोटे-छोटे कार्य जैसे ड्राईविंग लाईसेंस या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना हो तो वह भी नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में और खासकर मेरे हल्के में सड़कों की बहुत ही खस्ता हालत है। सड़कों पर गढ्ढे ही गढ्ढे नजर आते हैं। उन सड़कों पर बड़े-बड़े होल बने हुए हैं। मेरे हल्के में किसी सड़क पर आज तक तारकोल तो दूर कोई रोड़ी तक नहीं डाली गई। वहां पर सड़कों की ऐसी हालत है कि आप अपनी गाड़ी दूसरे गेयर से तीसरे गेयर में डाल कर नहीं ले जा सकते।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आज के दिन ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि मेरे हल्के में एक पुलिस स्टेशन के तहत एक डकैती डाली गई। उस डकैती का आज तक कोई पक्का सुराग सरकार नहीं लगा पाई। वहां पर 5 पिस्तौल एक कारतूसों से भरा थैला तो बरामद किया गया लेकिन उस केस में सिर्फ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है बाकी किसी को नहीं किया गया, जो दूसरे पकड़े गए थे उन सब को बरी कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि आज के दिन हमारे प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। इसी वजह से आज के दिन शाम के वक्त महिलाओं का अपने घर से निकलना बहुत ही दूभर हो गया है। जिन लोगों ने हमें वोट दिए थे उनको धमकाया जा रहा है। मेरे हल्के के जिन बनिया भाईयों ने मुझे वोट दिए थे उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोगों ने कांग्रेस को वोट क्यों दिए ? वे लोग डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह पा रहे। इसी प्रकार से महिलाओं में भी बराबर कर डर बना हुआ है। (विघ्न)

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्या जिस ढंग से बोल रही हैं वह ठीक नहीं है, इन्हें तमीज से बोलना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं और इनसे यह कहना चाहूंगा कि इन्हें ठीक तरीके से बोलना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। ये मन्त्री हैं और इनको किसी मेम्बर को बीच में नहीं टोकना चाहिए, जब इनका वक्त आएगा तो ये जवाब दे लें। (विघ्न)

श्री सुभाष चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि इनकी पहली स्पीच है इसलिए मैं इनकी स्पीच में इनको टोकना नहीं चाहता। मैंने आपके माध्यम से केवल इतनी ही बात कहनी है कि इन्होंने बनिया जाति की बात कही है इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा। (विघ्न)

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि शहीदों को दी जाने वाली राशि क्या केवल चुनाव तक ही थी ? आज वह राशि कहां चली गई है ? इलैक्शन के बाद वह किसे मिल रही है ? मुख्य मन्त्री जी की तो बात छोड़िये, कोई मन्त्री भी आज उनको पूछने के लिए नहीं जाता है, क्या वे शहीद नहीं हैं ? क्या यह मात्र चुनावी वायदा ही था ? उसके बाद कोई सरकारी अफसर तक भी उनके हाल-चाल पूछने के लिए नहीं गया। (विघ्न)

[श्रीमती अनीता]

जहां तक नालों की समस्या के बारे में सम्बन्ध है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि साल्हावास क्षेत्र में नहर का पानी नहीं चल रहा है लेकिन जब फसल पक कर तैयार खड़ी है तो फसल पकाने के नाम पर वहां पर नहरों में ज्यादा पानी छोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा सदन को बताना चाहूंगी कि इस वक्त कई गांवों में पानी खड़ा है जिससे फसल को नुकसान हुआ है इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उन किसानों को फसल का मुआवज़ा दिया जाए और जिन खेतों में पानी खड़ा है उस पानी को खेतों से निकलवाने का प्रबन्ध किया जाए ताकि किसान अगली फसल वहां पर बो सकें। अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी की बात बार-बार कही जाती है। मैं सरकार का ध्यान पीने के पानी की तरफ दिलाना चाहती हूं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की भारी दिक्कत है और वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कई बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है वहां पर एक कैण्टर आता है और 3/- रूपये एक पानी के घड़े का लिया जाता है। जो आदमी तीन रूपये का घड़ा लेकर पानी पिएगा उसका गुजारा कैसे होगा और उसको नहाने तथा कपड़े धोने के लिए पानी कहां से उपलब्ध होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप उन गांवों के नाम बताएं जहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

श्रीमती अनीता : मातन हेल और उसके साथ लगते कई बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जब तक चुनाव नहीं हुए थे तो मुख्य मन्त्री जी वायदा करते थे कि मुफ्त बिजली-पानी देंगे। हमारे हल्के में लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे जिसके कारण हमारे बिजली के कनैक्शन्ज़ कटे पड़े हैं। इसी प्रकार जिन लोगों ने बिजली के बिल्ज़ नहीं भरे उनके ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शन्ज़ भी कटे पड़े हैं। मेरे अपने ट्यूबवैल का बिल 20 हज़ार रूपये का था जो कि मैंने नहीं भरा और हमारा कनेक्शन भी कटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मुख्य मन्त्री जी को इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करनी चाहिएं। सारे हरियाणा को खुशहाल बनाने की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्य मन्त्री की बढ़ाई कर दी और दो-चार मन्त्री बन गए। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा के विकास की बात होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री गोपी चन्द (गुड़गांव) : माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कल अभिभाषण दिया वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है तथा उसमें एक नई दिशा जनता के लिए दी गई है। हरियाणा की जनता के लिए बहुत सी बातें इसमें रखी गई हैं। मैं विशेषकर गुड़गांव के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि मेरी नुमाईन्दगी गुड़गांव से है इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बातें रखूंगा क्योंकि गुड़गांव एक औद्योगिक क्षेत्र है। (विघ्न) मैं अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। यहां औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाया गया है। इन सात महीनों में विकास की गति को काफी बढ़ाया गया है वह बहुत ही सराहनीय है और प्रसंशनीय है। अध्यक्ष महोदय, जहां लोग उद्योग के लिए प्लाट लेने के लिए कई कई महीने इन्तजार करते रहते थे लेकिन आज आप जब चाहें प्लाट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब उससे अगले दिन ही उसको प्लाट दे दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में सी०ए०यू० के रेटस बढ़ा दिए गए थे जिससे उद्योग पलायन करने लग गए थे। मेरी सरकार से मांग है कि जो सी०ए०यू० के अनाप-शनाप रेट बढ़ाए गए हैं इनमें भी कुछ राहत दी जाए। एच०एस०आई०डी०सी० और हुडडा ने हमें बहुत ही रगड़ा मारा है।

एच०एस०आई०डी०सी० ने हमारे यहां पर जो विकास के कार्य करने के लिए कहा था। मैं चाहूंगा कि सरकार उस बारे में पता करके बताएं कि उन विकास कार्यों का क्या हुआ है ? सरकार किसानों की जो जमीन ले लेती है उसके बदले में उनको कोई जमीन दे ताकि वे दोबारा से बस सकें। उस जमीन से उनके बच्चों का चाहे वे दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दूसरे लोग हैं उनका गुजारा चलता था। उनकी जमीन सरकार द्वारा ले लिए जाने पर वे कुछ नहीं करते हैं। मैं यह कहूंगा कि 50 प्रतिशत के करीब उनको नौकरियां दी जाएं। वहां के जो श्मशान हैं, मन्दिर हैं और जो दूसरी जमीन है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। हुड्डा को नए सैक्टरों की बसाने की जो बीमारी है उसका एक एड्डीएशन है 'Harassment until death to allottee.'

अध्यक्ष महोदय, जो गन्ने के रेटस बढ़ाए गए हैं यह बहुत ही प्रसंशनीय कार्य है। इतिहास में ऐसे रेटस् कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने जो मुआवजा माफ करने की बात कही थी उस बारे में सर्वे किया गया तो यह कहा गया था कि इसमें 100 परिवार ही आते हैं। जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ था। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 17 गांवों के 1000 के करीब ऐसे परिवार हैं जिनका मुआवजा माफ नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से पहले की सरकार के वक्त में मन्दिर, श्मशान और दूसरी जगहों की भूमि अधिग्रहण कर ली जाती थी और बाद में अहसान करके थोड़ी-थोड़ी भूमि छोड़ दी जाती थी या पैसा लेकर के छोड़ी जाती थी। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जो खाली जगह हैं उसको ही लिया जाए श्मशान और मन्दिर आदि की जमीन छोड़ दी जाए। आज शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। हर शहर कंक्रीट का शहर बन रहा है। वहां पर जो तीन दर्जन गांव हैं वे आज स्लम बनते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले आठ सालों में कितने गांवों को विकास करने के लिए एडाप्ट किया गया और कितने गांवों में विकास के काम करवाए गए ? मुझे दुःख है कि एक भी गांव एडाप्ट नहीं किया गया। जो पहले से ही एडोप्टेड गांव थे उनमें भी विकास के काम नहीं करवाए गए इसलिए वे आज स्लम बनकर रह गये हैं। मेरा सरकार से कहना है कि उन गांवों को स्लम न बनने दिया जाए बल्कि हुडा का वहां पर एक एस०ई० बिठाया जाए। उन सभी गांवों में वैसी ही सुविधाएं दी जाएं जैसी वहां पर हुडा के सैक्टर्ज में दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्थानीय स्वशासन की बात है, मैं यही कहूंगा कि शहरों की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है लेकिन गुड़गांव जैसे शहर में जहां पर दिल्ली का भार बढ़ता जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है वहां पर आज जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं उनको अनअथोराइज्ड न कहा जाए बल्कि उनमें पूरी सुविधाएं दी जाएं क्योंकि वे कालोनीज वर्षों से बसी हुई हैं। इसी तरह से वहां के स्लम क्षेत्र के लिए भी विशेष पैसा दिया जाए।

वैसे तो ऐजुकेशन की तरफ काफी ध्यान दिया गया है और अभिभाषण में भी सौ से अधिक प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गयी है परन्तु ऐजुकेशन के मामले में यदि कोई जिला सबसे पिछड़ा है तो वह गुड़गांव है। गुड़गांव का मेवात एरिया ऐजुकेशन में बहुत पीछे है इसके लिए मैं किसको दोष दूं। अध्यक्ष महोदय, सन 1969 के बाद गुड़गांव बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर एक भी नया ऐजुकेशन इंस्टीच्यूट नहीं खोला गया है। पिछले 41 सालों में वहां पर कोई नया मैडीकल कालेज नहीं खोला गया, कोई नया लॉ कालेज नहीं खोला गया, कोई नया बी०एड० कालेज नहीं खोला गया और न ही लड़कियों के लिए कोई नया तीसरा कालेज खोला गया है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर एक मैडीकल कालेज एवं रीजनल सैंटर खोला जाए जिसमें उपरोक्त सभी तरह के कालेज हों। इसी तरह से एक डिग्री कालेज भी वहां पर खोला जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में कम्प्यूटर की सबसे ज्यादा मांग है

[श्री गोपी चन्द]

लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुड़गांव के साथ इस मामले में भी भेदभाव बरता गया है। पिछले साल विदेशी सहायता से लड़कियों के लिए जो कम्पयूटर कोर्सिज शुरू किये गये थे, गुड़गांव उसमें भी अभागा रहा क्योंकि वहां पर कम्पयूटर कोर्सिज शुरू नहीं किये गये। मैं चौटाला साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गुड़गांव की जनता की मांग पर अपने सात महीने के शासनकाल में वहां पर कम्पयूटर कोर्स खोले जिसमें 120 बहनों को दाखिला दिया गया। जिन जिन क्षेत्रों में भी गुड़गांव के साथ भेदभाव किया गया है उनकी तरफ सरकार विशेष तवज्जो दे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्पोर्टस की बात कहूंगा क्योंकि यहां पर कई स्पोर्टसमैन भी हैं और मैं भी स्वयं स्पोर्टसमैन रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 13वें एशियाड में जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था। मुझे फख्र है कि इन खिलाड़ियों में जो भारतीय महिला हाकी टीम की कप्तान प्रीतम ठाकरान नाम की खिलाड़ी थी वह मेरे ही गांव की थी लेकिन अफसोस यह देखकर हुआ कि छोटे छोटे राज्यों ने भी अपने खिलाड़ियों को सब कुछ दिया लेकिन हरियाणा ने अपने इन खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया। लेकिन अब मुझे फख्र है कि प्रीतम ठाकरान को पूरे हरियाणा का मैडल देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में स्पोर्टस के नाम पर बाबा आदम के जमाने का एक नेहरू स्टेडियम है। मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव की जनता की मांग पर एक स्पोर्टस कम्पलैक्स का उदघाटन किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। जहां तक उसमें ऐस्टो टर्फ स्थापित करने की बात थी उसको भी सरकार ने माना है जोकि एक अच्छा कदम है। मैं सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों में पहली बार हरियाणा में खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है।

अब खेल उत्सव आयोजित करके खेलों को प्रोत्साहन देने का अहम कदम उठाया गया है। मेरी सरकार से यह मांग है कि हमारे यहां जो 45 एकड़ क्षेत्र में स्पोर्टस कॉम्पलैक्स बना रहे हैं उसके साथ साथ पटियाला की तर्ज पर एक स्पोर्टस कालेज भी बनाया जाए जहां पर एन०आई०एस० की क्लासिज चलाई जा सकें।

अब मैं रोड्ज का जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली से गुड़गांव तक रोडज़ की वह हालत होती थी जो देखते ही बनती थी यह हालत किसी से छुपी नहीं थी उसमें काफी सुधार हुआ है। मेरी तो यही मांग है कि मेरे गुड़गांव क्षेत्र में खांडसा रोड है जिसमें बहुत बड़ी मंडी लगती है, 3-4-5 बार्ड लगते हैं, 30 परसैंट शहर की आबादी है और 10 गांव हैं इसके बावजूद भी किसी ने पिछले दो साल से इस रोड को ठीक करने की जरूरत नहीं समझी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे हल्के की खांडसा रोड को टॉप प्रायोरिटी पर ठीक करवाया जाए। सरकार का खजाना भरने में हमेशा गुड़गांव आगे रहता है लेकिन हमारे यहां आज तक मिनी सैक्रेटेरियट नहीं है। एक आफिस कहीं है और दूसरा कहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि गुड़गांव जैसे महत्वपूर्ण जिले में जो कि दिल्ली के नजदीक है वहां शीघ्र मिनी सैक्रेटेरियट बनना चाहिए ताकि सभी ऑफिस एक छत के नीचे आ सकें और वहां की जनता को अपने कार्यों के लिए इधर-उधर न जाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां की ट्रांसपोर्टेशन की हालत किसी से छुपी नहीं है। हम दिल्ली का बोझ सहन करते हैं। हमारे यहां ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत है। मेरा तो पुनः यही निवेदन है कि इस रोडवेज को बचा लो।

आज ला एण्ड आर्डर सबसे अहम बात है। अब तक इसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे गुड़गांव को भुगतना पड़ा है। गुड़गांव में बैंक लुटे, डाकखाने लुटे, मर्डर हुए और उसके विरोध में जब हम जैसे लोगों ने आवाज उठाई तो हम पर गोलियां चलाई गईं। डी-गैंग गुड़गांव के सभी प्रमुख व्यापारियों को धमकियां देती थी कि इतना पैसा नहीं दोगे तो यह कर दिया जाएगा, वह कर दिया जाएगा। गुड़गांव ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया था। पिछले कुछ महीने से मामला कुछ सुधरा है लेकिन यह इसी तरह से रहे बल्कि इसमें कुछ और सुधार लाने की आवश्यकता है। जहां तक विकास की बात है, दिल्ली के नजदीक हम हैं। चाहे फूलों की खेती का मामला हो या होर्टीकल्चर का हो, गुड़गांव से दिल्ली की मंडी नजदीक है और हमारे यहां खपत भी है इसलिए इस दिशा में काम किया जाए। इस अवसर पर मैं यदि मेवात के बारे में जिक्र नहीं करूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा। हमारे साथी कह रहे थे कि विधान सभा में पारदर्शिता नहीं है तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पहले से तो अब बहुत अच्छी सिचुएशन है। मेवात में जब महामारी आई थी उस वक्त 9 हजार आदमी उस महामारी में मरे थे। उस समय चौकीदारों के रजिस्टर छुपा लिए गए थे हम लोगों ने घर घर जाकर मृत लोगों की लिस्ट तैयार की थी और लीडर आफ दि अपोजीशन ने जब लिस्ट सदन के पटल पर रखनी चाही तो उसे रखने नहीं दिया गया और ये लोग पारदर्शिता की बात करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि मेवात ने आपकी झोली भरी है इसलिए मेवात क्षेत्र का आप बहुत ध्यान रखना। मेवात सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए इसको आप विकास में प्राथमिकता देना। नहरों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां मेवात कैनाल है। उसके बारे में हम बहुत कुछ कहते रहे मगर उस पर कोई काम नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि मेवात कैनाल पर अब काम होगा। माननीय चौधरी भजन लाल जी इस सरकार की कारगुजारियों के बारे में कुछ कह रहे थे तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी इस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन उचित नहीं होगा। मैं तो सड़कों पर घूमने वाला आदमी हूं और बी०ए० तक इतिहास का स्टुडैंट रहा हूं। इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा काम करने के लिए शेरशाह सूरी का नाम जाना जाता है। उस वक्त सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विकास के काम शेरशाह सूरी ने करवाए थे और उसके बाद अगर किसी ने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा काम करवाए हैं तो वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले सात महीने में करवाए हैं। मैं तो यही गुजारिश करूंगा इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है,। सभी आपस में मतभेद भुलाकर इस अभिभाषण को थम्पिंग मैजोरिटी से पारित करें। धन्यवाद।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन को अभिभाषण के माध्यम से सम्बोधित करके हमें कृतज्ञ किया है। आज उनके अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। मैं इस अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपने दृष्टिकोण से इस सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं और इस अभिभाषण में सरकार का जो संकल्प है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही मैं इस सरकार से स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो अपेक्षाएं हैं उनका भी अपने भाषण के माध्यम से समावेश करना मेरा नैतिक कर्त्तव्य बनता है। सर्वप्रथम तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज चौधरी देवी लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर पहली बार इस सरकार का सहकारिता व रचनात्मक दृष्टि से वोटिंग के आधार पर निर्माण करवाया है उसके लिए यह सारा सदन, पूरा हरियाणा और हम विशेष रूप से उनके आभारी हैं। इस बात का श्रेय वर्तमान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए वे शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए हैं। सरकार ने पहली बार इस प्रदेश में वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव करवाये इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। मैं यहां

[श्री भगवान सहाय रावत]

पर एक पंक्ति और जोड़ना चाहता हूं कि जब भी इस प्रदेश में कोई चुनाव हो सरकार उसमें वोटिंग मशीन का उपयोग करे तो सभी दिक्कतों से हमें छुटकारा मिल जायेगा यह मेरा सरकार से निवेदन है। जैसा कि आदरणीय चौटाला साहब ने एस०वाई०एल० नहर के निर्माण के बारे अपने भाषण में उल्लेख किया और माजरा साहब ने भी इस बात का उल्लेख किया और हमारे आदरणीय साथी श्री गोपी चन्द गहलोत ने भी हरियाणा प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था के बारे में खासकर दक्षिणी हरियाणा के मेवात क्षेत्र की मेवात कैनाल के बारे में जिक्र किया। वे आगरा कैनाल को शायद भूल गये। इसके बारे में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० के निर्माण के बारे में यह सरकार संकल्प ले और साथ में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से विचार-विमर्श करके इस बारे में एक प्रस्ताव पास करे और केन्द्र सरकार को इस नहर के निर्माण के बारे में आग्रह करें यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की निरर्थक बातों में न पड़ते हुए कि पहली सरकार ने यह नहीं किया वह नहीं किया सीधे ही एक प्रस्ताव परित करे तो मेरे ख्याल से उसके लिए यह सारा सदन और हम सब इस बात के लिए तत्पर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अगर पिछले शासनकाल के समय ही और चौटाला साहब के अब के शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में वर्तमान और भविष्य की उपलब्धियों के बारे में जिक्र करूं तो शायद इस सदन में काफी समय लग जायेगा। परन्तु इस बात की पुष्टि हमें चुनाव के दौरान देखने को मिली। जब हम चुनावों के दौरान हरियाणा प्रदेश के गांवों में जाते थे तो हर गांव का पांच साल का बच्चा भी चौधरी देवी लाल जी के नाम से परिचित था और जो प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे उनमें वे चौधरी देवी लाल की छवि को देखकर हर गांव का बच्चा उनका नाम ले रहा था। इसके बाद मैं बुढ़ापा पैंशन के बारे में कहना चाहता हूं। पाश्चात्य जगत के जो बुद्धिजीवी बनते हैं और जो कम्युनिस्ट डोमीनेटिड देशों में रह रहे हैं उन्होंने भी इस समान दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जो चौधरी देवी लाल जी ने बुढ़ापा पैंशन सम्मान स्वरूप बुजुर्ग लोगों को देकर एक अहम् कार्य किया है। मैं चौटाला साहब का आभारी हूं कि उन्होंने बुढ़ापा पैंशन को दुगना कर दिया है और दूसरी विकलांग पैंशन और बेरोजगारी भत्ते को भी बढ़ाया है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भगवान चौधरी देवी लाल जी को लम्बी उम्र दे और वे 100 साल तक जियें जिन्होंने बुजुर्ग लोगों को बुढ़ापा पैंशन जैसा सम्मान दिया। मैं तो चौटाला साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इस बुढ़ापा पैंशन को हर साल 100/- रुपये बढ़ाते रहें तो इससे ज्यादा और जन-कल्याणकारी कार्य कोई हो ही नहीं सकता। चौधरी बंसी लाल जी शायद सदन में मौजूद नहीं हैं परन्तु उनका एक विधायक तो शायद मौजूद होगा। मैं चौधरी बंसी लाल जी को इस समय याद दिलाए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि उनके शासनकाल में जब उन्होंने शराबबंदी लागू की तो इस देश का भविष्य और देश की जिम्मेवारी जिन नौजवानों के कन्धों पर होती है वे अपने कर्त्तव्य-निष्ठा से अलग हटकर शराबबंदी की आड़ में तस्करी के विनाशकारी मार्ग पर चल पड़े क्योंकि उनके भविष्य का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं

11.00 बजे

था। मैं समझता हूं उस वक्त हमारे विपक्ष के साथियों ने और विपक्ष के नेता ने और आर्यसमाज जैसी सामाजिक संस्थाओं ने इसकी सराहना की थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शराबबन्दी के पीछे एक सूक्ष्म दृष्टि छिपी हुई थी जिसको आप सभी जानते हैं कि शराबबन्दी के बाद नौजवान पीढ़ी रास्ता भटककर नाजायज शराब बेचने के धन्धे में फंस गई थी। बूढ़े मां-बाप जिनकी आंखों में अपने बच्चों के भविष्य का सुन्दर सपना था, अपने बच्चों की गरीबी की मार के कारण आत्मनिर्भर नहीं बना पाए थे। बेरोजगारी से विवश होकर अपने बच्चों को ऐसा काम करने से रोक नहीं पाए। ऐसे नौजवानों पर पिछली सरकार ने मुकद्दमे बना दिए थे। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने आते ही उन सारे केसिज को वापिस लेकर उनके साथ बहुत न्याय किया है। मैं समझता हूं कि परमात्मा ने उन्हें

एक मौका दिया है कि वे अपने आप को आत्म-निर्भर बना सकें और देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में बनी हमारी पार्टी की सरकार का यह संकल्प है कि हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से बाढ़ रहित प्रदेश बने। हमारे मेवात और हथीन क्षेत्रों में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर सेम और बाढ़ की बहुत भयानक समस्या है, उन इलाकों के बारे में माननीय सदस्य श्री गोपी चन्द जी ने भी सदन में बोलते हुए बताया था कि मेवात एरिया में बाढ़ आई थी तो उस समय चौ० देवी लाल मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वहां किसानों को उनकी खड़ी फसलों का मूल्य देकर एक बहुत ही अच्छा काम किया था उसके बाद परमात्मा की कृपा से मेवात एरिया में आज तक बाढ़ नहीं आई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 40-45 वर्ष के शासन के बाद भी यहां पर निरन्तर बाढ़ और सूखा दोनों साथ-साथ चलते हैं। एक दीर्घगामी योजना बनाई जाए जिसमें बाढ़ के पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था हो जाए दूसरी तरफ सूखे की स्थिति से निपटा जाए। पिछली सरकार की उपलब्धियों का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि पिछली बार बाढ़ और सूखे से दक्षिणी हरियाणा में जो स्थिति हुई थी उसको चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने बखूबी निपटाया है। पिछली सरकार की तुलना में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन इस सरकार के समय में हुआ है। कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी थोड़ी है और यदि चर्चा न की जाए तो मैं समझता हूं कि अपने कर्त्तव्य के प्रति कोताही होगी। अग्रोहा मैडिकल कालेज उनमें से एक है। मैं समझता हूं कि चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में 36 बिरादरी के लोग हैं। चौ० देवी लाल जी का अपना एक व्यक्तित्व है जो आज जगत ताऊ के रूप में प्रसिद्ध हैं और हरियाणा में बैठे हुए जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, वे उनके राजनीतिक गुरू हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि अधिकांश सदस्य चौ० देवी लाल जी की देन हैं। चौ० देवी लाल जी के चरणों में बैठकर जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उस व्यक्तित्व के सामने हरियाणा नहीं बल्कि पूरा देश आज राजनीतिक दिशा ले सकता है। इन्होंने पिछली सरकार के द्वारा बन्द की गई अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट को बहाल करके अग्रवाल बिरादरी का जहां सम्मान बढ़ाया है वहीं पर इस हरियाणा के छात्रों को, हरियाणा की युवा पीढ़ी के मैडिकल स्टूडैंट्स को 20वीं सदी का तोहफा दिया है। 5100/- रुपये कन्यादान की राशि के रूप में देकर इस सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। आप सभी लोग इस बात को भली-भान्ति जानते हैं कि गरीब मां-बाप अपनी लड़की की शादी योग्य आयु होने के बाद कितने चिन्तित रहते हैं और सोचते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे सरकार से उसके घर जाकर 5100/- रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी, यह गरीब की बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। अभी बहन अनीता जी कह रही थीं कि यह कोरा झूठ है तो मैं उनकी बात से असहमत होता हुआ कहना चाहूंगा कि भाई-बहन के रिश्ते से कोई पवित्र रिश्ता नहीं होता है। बाप-बेटी के रिश्ते से पवित्र कोई रिश्ता नहीं होता है। हर मां-बाप की इच्छा होती है कि उसकी बहन, उसकी बेटी अच्छी तरह से ससुराल जाए। इस कन्यादान योजना की इन्हें प्रशंसा करनी चाहिए थी। अगर बीच में प्रशासनिक दृष्टि से कोई बात है तो मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहिए था।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, भगवान सहाय जी जो कुछ भी कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। यह पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैडम प्लीज आप बैठिये।

श्री भगवान सहाय रावत : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बहन जी को कहना चाहूंगा कि ये इस तरह से मुझे बोलते हुए बीच में रुकावट न डालें और जो कुछ भी कहें वह चेयर की अनुमति लेकर ही कहें। स्पीकर सर, जो 5100/- रुपये की राशि कन्यादान के लिए गरीबों को दी जाती है यह उनका

[श्री भगवान सहाय रावत]

बहुत बड़ा सहारा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि मैं किसी की भी अनावश्यक प्रशंसा नहीं करता। जो बात सही होती है उसे सही कहता हूं और जो गलत होती है उसे गलत कहता हूं। स्पीकर सर, बुढ़ापा पैंशन में प्रशासनिक कमी की वजह से 70 साल के बुजुर्गों को तो पैंशन नहीं मिलती लेकिन जो 50 साल के या 55 साल के हैं उन्हें मिल रही है। इसी तरह से वोटर लिस्ट में भी कुछ प्रशासनिक कमियां हैं। स्पीकर सर, ये कमियां तभी दूर हो सकती हैं जब स्थानीय नेता जागरूक होंगे। एक जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए। जिसमें सभी जनता के प्रतिनिधि, अधिकारी, गांव के सरपंच और पंच इकट्ठे होकर लोगों को जागरूक करें तभी लोगों को अच्छा दिशा निर्देश मिल सकता है। स्पीकर सर, गन्ने के मूल्य में वृद्धि करके चौटाला साहब ने बहुत ही सराहनीय काम किया है क्योंकि गन्ना किसानों की प्रिय फसल होती है। ज्यादातर किसान गन्ने की बिजाई करते हैं। मैं किसान के यहां पैदा हुआ हूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गन्ने की बिजाई एक बार ही की जाती है। दूसरी फसलों की तरह इसकी बिजाई बार-बार नहीं करनी पड़ती। किसान एक बार गन्ने की बिजाई करके निश्चिंत हो जाता है और न ही गन्ने की फसल में रिस्क होता है। स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त में किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिला और किसान गन्ने को अपने खेतों में ही जला देते थे। लेकिन चौटाला साहब ने किसानों को गन्ने का उचित मूल्य देकर सराहनीय काम किया है। स्पीकर सर, मैं मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड के बारे में 3-4 बातें और कहना चाहूंगा जैसा कि चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड का गठन उनकी सरकार के समय में हुआ। स्पीकर सर, जब 1987 में मैं विधायक बनकर आया उस समय मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड में 6 ब्लॉक पड़ते थे और हथीन उनमें से एक है। उस वक्त चौटाला साहब मुख्यमंत्री होते थे। तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि चौटाला साहब आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड की कार्य प्रणाली पर दृष्टि डाली जाये। स्पीकर सर, चौटाला साहब ने तुरंत मेरी बात स्वीकार करके सभी सम्मानित मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाकर इस बारे में एक मीटिंग की। स्पीकर सर, चौटाला साहब ने उस समय अधिकारियों से पूछा था कि आप यह बतायें कि पिछली सरकार ने ब्लॉकवाईज मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड में कितना पैसा खर्च किया है। दुर्भाग्यवश पिछली सरकार ने हथीन में सिर्फ 2% पैसा ही खर्च किया था। स्पीकर सर, मेवात माडल स्कूल उस समय केवल दो ब्लॉक्स में ही होते थे। मैंने चौटाला साहब से आग्रह किया कि चौटाला साहब मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड पिछड़े हुए इलाके के लिए बनाया गया है इसलिए हमारे यहां 6 के 6 ब्लॉक्स में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। स्पीकर सर, इस बात के लिए मैं चौटाला साहब को बधाई दूंगा कि उस समय इन्होंने बजट को 6 हिस्सों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए 17% के हिसाब से पैसा दिया। चाहे वह हथीन हो, चाहे तावडू हो, चाहे फिरोजपुर झिरका हो, चाहे पुन्हाना ब्लॉक हो। सभी ब्लॉक्स को बराबर हिस्सा दिया गया था। स्पीकर सर, हमारे वहां ब्लॉक लैवल पर 2 माडल स्कूल होते थे। मैंने इस बारे में उस समय चौटाला साहब से आग्रह किया कि सभी ब्लॉक स्तर पर माडल स्कूल बनायें जायें और चौटाला साहब ने हर ब्लॉक हैडक्वाटर पर 6 स्कूल खोल दिये। लेकिन पिछली सरकार ने दोबारा से डी०पी०एस० के तहत इन 6 स्कूलों में से 2-3 स्कूलों को ही कंवर्ट किया। स्पीकर सर, मैं फिर से चौटाला साहब से आग्रह करूंगा कि वहां पर दोबारा से मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड के तहत सभी स्कूलों को डी०पी०एस० जो दिल्ली की सोसाईटी है उन्हें उसके अंडर करने का प्रयास करें ताकि मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड के तहत हर ब्लॉक ठीक रूप से लाभान्वित हो सके। स्पीकर सर, मैं एक शिक्षक रहा हूं और विधायक बनने का मुझे दोबारा अवसर मिला है। मैं आपके माध्यम से यहां के जो सदस्य हैं, मंत्रिगण हैं और विशेषतौर से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षक का मां-बाप के बाद तीसरा स्थान होता है। इस देश का नव

निर्माण महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और चौधरी देवी लाल जैसी शख्सियतों ने किया जिन्होंने भारत की आजादी के बाद पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति तथा भारत की सभ्यता और संस्कृति का विश्लेषण किया था। आज अगर मैं एक शिक्षक और विधायक के नाते उनका विशलेषण करूं तो हमारी सभ्यता और संस्कृति कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हमारी प्राचीन गुरूकुल पद्धति में राजा और गरीब को बराबर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और इसी कारण उनमें अच्छी संस्कृति होती थी व माताएं भी शिक्षित होती थीं तथा स्वयंवर की प्रथाएं होती थीं। स्पीकर सर, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यह भाषा उस समय बगैर किसी जाति या साम्प्रदायिक भेदभाव के शिक्षा देने का माध्यम होती थी। मुझे राजा भोज की वह बात याद आती है जब वहां के एक साधारण से आदमी ने राजा भोज को संस्कृत में अशुद्ध बोलने पर टोक दिया था। इस तरह की भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारी होती थी। आजादी के 40 साल के बाद आज मैं एक विधायक के रूप में और पहले शिक्षक के रूप में यह कहना चाहूंगा कि अगर इन 40 सालों में प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर शिक्षा नीति पर ध्यान दिया होता तो आज देश के नौजवानों का वर्तमान और भविष्य और उज्जवल होता। यह बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। मैं आज आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा में एक यूनीवर्सिटी का अभाव है। यहां पर कुरूक्षेत्र यूनीवर्सिटी, हिसार यूनीवर्सिटी और रोहतक यूनीवर्सिटी हैं तथा रोहतक हमारे दक्षिण हरियाणा का एजुकेशन सैन्टर रहा है। चौधरी साहब ने जब पलवल में दरबार लगाया था तो वहां पर यूनीवर्सिटी खोलने का आश्वासन दिया था। वहीं पर मेरा पैतृक गांव है और मैं यह इसलिये नहीं आग्रह कर रहा हूं कि वहां पर मेरा गांव है बल्कि मैं इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि वहां पर 900 बीघा जमीन पड़ी हुई है उसमें से हम 200 बीघा या 400 बीघा जितनी भी जमीन चाहे यूनीवर्सिटी के लिये फ्री ओफ कोस्ट देने के लिए तैयार है। पंचायत की पहले भी जमीन देने की ऑफर थी और आज भी है। इसलिये मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर रिजनल सैन्टर या एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी की स्थापना की जाए। आज हाथ जोड़कर फिर मैं चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी से आग्रह कर रहा हूं कि चौधरी देवी लाल जी आपके पिता हैं लेकिन वे जगत ताऊ भी हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं, वे इस सदन के अधिकांश राजनीतिक लोगों के गुरू हैं। वे हरियाणा प्रदेश से प्रथम बार उप प्रधानमंत्री रहे और इस पद को सुशोभित किया, वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। अरावली हिल्ज़ पर अब तक दूसरे काम होते हैं, जहां अरावली हिल्ज़ पर लोग प्रोपर्टी डिलिंग्ज तो कर सकते हैं लेकिन गुरूकुल जैसी संस्था और जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी के समानान्तर एक यूनीवर्सिटी की मांग उन्होंने कभी नहीं की। जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी में हमारे आई०ए०एस० और आई०पी०एस० तैयार होते हैं। हमारे उधर भी इसी तरह के रिजनल सैन्टर की स्थापना आदरणीय चौधरी देवी लाल जी के नाम पर की जाए जिससे सारे फरीदाबाद, गुड़गांव तथा दक्षिणी हरियाणा बल्कि मैं यह कहूंगा कि समस्त हरियाणा लाभान्वित होगा और सभी विधायक-गण भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा प्रभाव है जो कि इसमें एक माइनस प्वाईंट है। ग्रामीण परिवेश में पले हमारे बच्चे और बच्चियां चौधरी देवी लाल के दर्शन में ग्रामीण आंचल में पैदा होकर ग्रामीण और धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उनके शुभ ग्रन्थ और उनकी जो थ्योरी है वह देश को एक नई दिशा देती है। उस रिजनल सैन्टर में बच्चे शुभ ग्रन्थों पर अपने दृष्टिकोण से रिसर्च करेंगे। हरियाणा की इस धरती पर जहां शहीदों ने नाम कमाया है वहां हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि केन्द्र में वाजपेयी जी की सरकार है और वे बहुत सात्विक प्रवृति के हैं। उनके सहयोग से चौधरी देवी लाल जी के नाम पर पलवल में एक यूनीवर्सिटी के रिजनल सैन्टर की स्थापना की जाए जिससे अरावली हिल्ज में बसने वाला पूरा गुड़गांव,

[श्री भगवान सहाय रावत]

फरीदाबाद, सारा दक्षिणी हरियाणा और मेवात का एरिया लाभान्वित होगा। दिल्ली में जो हवाएं चलती हैं जिसमें सारे भारत की नौजवान पीढ़ी बसती है, वहां की लेटैस्ट टैकनोलोजी, लेटैस्ट पुस्तकें और सुविधायें इस रिजनल सैन्टर में उपलब्ध हो सकती हैं। हमारे हरियाणा की युवा पीढ़ी इस रिजनल सैन्टर का पूरा लाभ उठा सकेगी। अन्त में, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय दिया। सबसे पहले तो इस हरियाणा की विधानसभा के चुनाव नजरिये पर नजर डालें तो पिछले लगभग 7 महीने से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनैलो-भाजपा गठबन्धन की सरकार जो कि 24 जुलाई 1999 से सत्ता में आई थी और आने के बाद लगभग 1 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और उन चुनावों में हरियाणा के लोगों ने 85 सीटों पर इनैलो-भाजपा गठबन्धन को बढ़त दिलाकर विजय दिलाई थी। सिर्फ इस बात को देखते हुए जनता ने उन्हें विजय दिलाई थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष के नेता हैं इसलिये हरियाणा के लोगों को उनसे बहुत आशाएं थीं क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रान्त का उद्धार होगा और किसानों का भला होगा। इस सरकार को चुनाव होने तक बने हुए सात महीने हो गए थे। इन सात महीने के दौरान जो नतीजे चुनाव के इनैलो व भाजपा के पक्ष में आये उन पर दोनों को मिलाकर 53 सीटें मिली। मैं समझता हूं कि ये 53 सीटें भी इसलिए आई क्योंकि इनकी सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, चुनावों के दौरान चुनाव आचार-संहिता का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ था। सभी को पता है कि वृद्धावस्था पैंशन की बढ़ी हुई राशि उसी समय दी गई। चुनावों के दौरान ही गांवों में खम्भे व तारें भेजी गई ताकि लोग यह समझें कि सरकार हमारे लिए बिजली की पूरी व्यवस्था कर रही है। इसी प्रकार से कहीं पर बिल्डिंगें बनाये जाने के लिए ईंटें भेजी गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनाव आचार-संहिता का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन सरकार द्वारा हुआ है। चुनावों के दौरान सरकार की तरफ से झूठे प्रलोभन दिए गए। चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि एस०एस०एस० बोर्ड का चेयरमैन आपके हल्के का बना दिया है, वह आपके बच्चों को नौकरी देगा। इसी प्रकार से पुलिस में भर्ती करने के लिए पहले ही लोगों की छातियां व कद नाप लिए ताकि उनको प्रलोभन दिया जा सके कि उनकी पुलिस में भर्ती हो जाएगी। ऐसे प्रलोभन देकर भी इन चुनावों के दौरान भाजपा तथा इनैलो गठबंधन केवल 53 सीटें ही प्राप्त कर पाया। मेरा तो भाजपा को सुझाव है कि जिस प्रकार के नतीजे जिस ढंग से आये हैं उनको ध्यान में रखते हुए भाजपा को सरकार से अपने सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि इनका एक गठबंधन न होकर यह एक धोखेबाज का गठबंधन था। हमारे माननीय साथी श्री कृष्ण पाल गुर्जर फिर भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप मेरा पिछला रिकार्ड उठा कर देख सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से अच्छे काम हुए हैं चाहे वह बंसी लाल जी की सरकार रही है या चौटाला साहब की सरकार रही है, उन अच्छे कामों की मैंने तारीफ की है। आगे भी मौजूदा सरकार जो अच्छे कार्य करेगी उनकी मैं तारीफ अवश्य करूंगा। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चाहे कोई भी सरकार है अगर वह अच्छे कार्य करती है तो हम सभी को उनकी सराहना करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरिजन भाइयों की बेटियों के लिए कन्यादान के तहत 5100/- रुपये देने की जो स्कीम चलाई हुई है उस पर सरकार को दुबारा विचार करना चाहिए क्योंकि इस समय जो कायदे कानून बने हुए हैं उनके तहत उन गरीब हरिजन भाइयों को इस स्कीम का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस अच्छी स्कीम के बारे में पुनर्विचार करते हुए नियमों में कुछ सुधार करें ताकि उनको इस स्कीम का फायदा मिल सके। इस में एक रुकावट तो उम्र की आती है। नियमों

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

के हिसाब से तो केवल जिस लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होगी उसको इस स्कीम का फायदा मिल सकेगा लेकिन आप सभी जानते हैं कि देहात में कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की 18 साल की उम्र होने तक शादी करने के लिए इन्तजार नहीं करता। देहात में आमतौर पर 15-16 साल की उम्र में ही लड़की की शादी कर दी जाती है।

नगर एवम् गांव आयोजना मंत्री (श्री बीरपाल सिंह) : नरेन्द्र सिंह जी, आपको पता ही है कि यह तो संविधान में लिखा है कि 18 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह : आपकी बात से मैं सहमत हूं लेकिन इस पर पुनर्विचार करते हुए कोई न कोई रास्ता सरकार अवश्य निकाले ताकि उन गरीब हरिजनों को इसका फायदा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं। ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार किसानों की सरकार है। इसी नाम पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में और मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार ने जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है उसमें उर्वरक महंगे किए गए हैं जिनका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा जिससे महंगाई भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भी जो राशन मिलता था वह भी केन्द्र सरकार के बजट में मंहगा हो गया है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वे केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो वस्तुएं महंगी होगी उनको महंगी न होने दें और उनके जो मूल्य पहले थे वे रहने देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस अभिभाषण में एस०वाई०एल० का जिक्र आया है। मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० दक्षिण हरियाणा के लिए एक जीवन रेखा है। क्योंकि उसका पानी हमारे इलाके में आना है। डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और दादरी के अन्दर इसका पानी आना है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस मामले को चलते हुए बहुत साल हो गए हैं। इस अभिभाषण के अन्दर भी यह लिखा हुआ है कि इराडी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्पलीमैंट करने के लिए हमारी सरकार केन्द्र सरकार को लिखेगी तथा उसे मजबूर करेगी कि वह इस आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए उस फैसले को शीघ्र ही लागू करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमन्त्री जी का पंजाब के मुख्यमन्त्री जी से बहुत नज़दीकी सम्बन्ध है। इस बात को सारा हिन्दुस्तान जानता है। केन्द्र सरकार के अन्दर भी इस सरकार की हिस्सेदारी है। परमात्मा ने और हरियाणा की जनता ने इस सरकार को काम करने का मौका दिया है। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि मेहरबानी करके किसी प्रकार से एस०वाई०एल० कैनाल का जो काम बचा हुआ है, केन्द्र सरकार की किसी एजैंसी के माध्यम से उस काम को करवाने की कृपा करें ताकि हमारे इलाके के अन्दर भी पानी की सुविधा मिल सके। नहरी पानी की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकार के मुखिया चौधरी बंसी लाल जी भी कहा करते थे कि हमारा उद्देश्य अन्तिम छोर तक टेल ऐण्ड तक पानी पहुंचाना है और यह पानी पहुंचाया जाना चाहिए था परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि मेरे हल्के के अन्दर ताकीखेड़ा और नांगल चौधरी के इलाकों में आज तक नहर का पानी नहीं पहुंचा है इसलिए मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह इस बारे में ध्यान दे और जिन क्षेत्रों में आज तक नहरी पानी नहीं जा सका है उन क्षेत्रों में नहरी पानी पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नहरों के अन्दर जो पानी चल रहा है उसका जिलावाईज़ हिस्सा कम से कम हम को मिलना चाहिए। हरियाणा के तमाम जिलों में जिस रेशो से पानी जा रहा है महेन्द्रगढ़ जिले के लिए भी उसी

[श्री नरेन्द्र सिंह]

अनुपात में हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। जब तक एस०वाई०एल० कैनाल का पानी नहीं आता तब तक पानी में हमें हमारा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सबसे मुख्य विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो 29 नगरपालिकाएं हमारी मौजूदा सरकार ने भंग की हैं उनसे एक गलत सन्देश जनता में गया है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति चाहे वह गांव में रहता है या शहर में वह यह महसूस करता है कि हमारी तरक्की होगी और हम कुछ ऊपर उठेंगे। जो 29 नगरपालिकाएं भंग की गई हैं उनमें अधिकतर हमारे विपक्ष के विधायक हैं। चाहे वह बरवाला हो, चाहे तावडू हो या अटेली हो अथवा कनीना हो यहां सभी जगहों से विपक्ष के विधायक चुनाव जीत कर आए हैं इसलिए लोगों के अन्दर एक सन्देश गया है कि हमने अपोजीशन पार्टी का एम०एल०ए० बना दिया है इसलिए हमारी नगरपालिकाएं भंग कर दी गई हैं। भले ही चौटाला साहब कहें कि ऐसी बात नहीं है लेकिन यह एक वास्तविकता है। अटेली के लोगों को तो इस सरकार से यह उम्मीद थी कि वहां पर और अधिक विकास के कार्य होंगे। चौटाला साहब को सभी जातियों ने मिल कर वोट दिए हैं कम से कम यहां पर एस०डी०एम० को तो बिठाएंगे और सब-डिवीज़न बनाएंगे। मैं कांग्रेस सरकार तथा चौधरी भजन लाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमन्त्री काल में एक नहीं बल्कि दो-दो तहसीलें बनाई। (विघ्न) मुख्यमन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। अगर नगरपालिकाएं घाटे के अन्दर चल रही हैं तो सरकार को चाहिए कि इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए। चौधरी सम्पत सिंह जी जैसे काबिल वित्त मन्त्री हमारे पास हैं इसलिए मैं उनसे यह चाहूंगा कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वे नगरपालिकाएं घाटे से उभर कर प्रोफिट में आ सकें। अगर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। वहां के लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिएं थीं। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि जो नगरपालिकाएं भंग की गई हैं उनको फिर से बहाल किया जाए।

स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा विशेष प्रावधान नज़र नहीं आया कि सरकार ने लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए स्ट्रैस किया हो या इस बात पर दबाव डाला हो कि हम हरियाणा के बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देंगे या बेरोजगारी को मिटाने के लिए कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं। आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि हरियाणा के अन्दर विशेषतौर पर देहात के अन्दर सैंकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बेरोजगार लोग हैं। उन बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने का कोई विशेष प्रोविजन करें। इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं जैसे कि महेन्द्रगढ़, इन पिछड़े हुए इलाकों को ज्यादा से ज्यादा सबसिडी दी जानी चाहिए ताकि बाहर के उद्योगपति आ कर हमारे इलाके के अन्दर उद्योग लगा सकें। गांवों के सभी लोगों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम उनको कोई रोजगार तो मिलना चाहिए। चाहे वे लोग आई०टी०आई० ट्रेंड हों, चाहे दूसरे पढ़े-लिखे लोग हों उनको फैक्टरीज़ के अन्दर रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा जो स्टेट हाईवे बने हैं जैसे कि रोहतक से नारनौल कोटपुतली को जो रोड निकलता है या जो दिल्ली रिवाड़ी से नारनौल होते हुए दूसरे प्रान्तों में गुजरात या राजस्थान के अन्दर जाता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप केन्द्र सरकार से प्रस्ताव करें कि इन स्टेट हाईवेज़ को नेशनल हाईवेज़ बनाया जाए ताकि उनके साथ लगती किसानों की जो जमीन है उसका अच्छा भाव उनको मिल सके। अगर ये रोडज़ बनेंगी तो मैं समझता हूं कि इससे किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में जरूर कार्यवाही करेगी क्योंकि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एम०एल०ए० ग्रान्ट के बारे में कहना चाहूंगा वर्ष 1991-96 में कांग्रेस सरकार के समय सभी विधायकों के लिए यह ग्रान्ट दी गई थी चाहे वह विपक्ष से थे चाहे सत्ता पक्ष से थे सभी पार्टियों के विधायकों को करीब 50 लाख रुपये की ग्रान्ट मिला करती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब विपक्ष में हमारे साथ बैठते थे तो वे भी कहा करते थे कि विधायक ग्रान्ट जरूर बहाल की जानी चाहिए। उस समय किसी भी कारण से वह ग्रान्ट बन्द की गई थी। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खुद मुख्यमन्त्री हैं इसलिए उसे बहाल करने की कृपा करें। प्रजातंत्र के अन्दर हर विधायक को मौका मिलता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करे। हम लोगों का यह फर्ज और धर्म बनता है कि, चाहे कोई विधायक सत्तापक्ष से हो या विपक्ष के हों सरकार से पुरजोर मांग करे कि जब मुख्यमन्त्री जी सोमवार को अपना रिप्लाई दें तो इस ग्रान्ट को हर हाल में बहाल करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों या अपोजिशन के विधायक हों वे सब इससे राजी होंगे। इसके साथ ही पिछली सरकार ने जो पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू की थी तो उस समय कुछ विभाग छोड़ दिए गए थे। जैसे हरियाणा हरिजन कल्याण और वैकवर्ड क्लासिज निगम हैं। इनको इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि ये घाटे में चल रहे थे। अब कल कोई हास्पीटल घाटे में चलेगा तो क्या उसको भी छोड़ दिया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि वे जो कारपोरेशंज या बोर्डज हैं इनके कर्मचारियों को भी पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा डवैल्पमैंट की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे महेन्द्रगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमन्त्री जी आप अपनी नजर समान रखते हुए सभी क्षेत्रों का एक जैसा विकास करने की कृपा करें। आज महेन्द्रगढ़ सारे हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है आप इसकी डवैल्पमैंट करवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान शिक्षा की तरफ दिलाना चाहूंगा। आज हरियाणा में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारे जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं उनके बच्चे भी प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इसका क्या कारण है कि आज बच्चे सरकारी स्कूलों की बजाए प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं जबकि वहां पर फीसें भी ज्यादा हैं। आप काबिल आदमियों के द्वारा इस बारे में जांच करवाएं कि क्यों हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप एक अहीरवाल विकास बोर्ड बनवाएं जैसे मेवात और शिवालिक बोर्ड हैं। यहां सदन में समय समय पर इस बारे में मैम्बर्ज द्वारा मांग की जाती रही है कि अहीरवाल बोर्ड बनाया जाए और इसके लिए भी केन्द्र से राशि आए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

अध्यक्ष महोदय, आज सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर सड़कों की तो बहुत ही बुरी हालत है। वहां पर गाड़ियां तो दूर रही साईकल वाला और पैदल आदमी भी नहीं चल सकता है। मेरे हल्के में नसीबपुर से धसू और हाजीपुर तक आने जाने का रास्ता ही बंद पड़ा हुआ है। इस तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि जिला महेन्द्रगढ़ को पूरा सम्मान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम भगत (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां सदन में रखा है मैं उसका हार्दिक रूप से उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण में

[श्री राम भगत]

हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और यह हरियाणा के चहुमुखी विकास को नई दिशा देने में एक कारगर कदम है। मैं इस बीज के लिए हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि इन्होंने, इसमें गांधी जी और चौधरी देवी लाल जी की जो प्रशासनिक शैली है, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। मुख्य रूप से सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है वह हरियाणा तथा देहात के विकास के लिए एक कारगर परियोजना है। यह कार्यक्रम वास्तव में देहात में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है। पिछले सालों में देखने को मिला कि गरीब किसान, गरीब मजदूर को चंडीगढ़ तक पहुंचने में या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक पहुंचने में और अफसरशाही का मुकाबला करने में बहुत परेशानी होती थी इसलिए वास्तव में सरकार ने इस पंचायती राज के माध्यम से गांधी राज की शुरूआत की है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे इस दस्तावेज में मुख्य रूप से तीन चार स्कीम्ज का जिक्र किया गया है जिनका संबंध सीधा मेरे हल्के के साथ है। अध्यक्ष जी, मैं यहां इस महान सभा में अपने हल्के नारनौंद के बारे में विशेष रूप से अपनी वेदना को प्रकट करना चाहता हूं। पिछले तीस सालों में अलग-अलग सरकारें आयीं और अलग-अलग चुनाइन्दे भी आये सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी लेकिन उस हल्के की तरफ किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। 1995 में वहां पर जबरदस्त बाढ़ आयी थी। इस बाढ़ में मेरे हल्के का पूर्वी हिस्सा जिसमें मुख्य रूप से बात, वाडाला, मौल पूठ्ठी गगनखेड़ी, खाडा, खराना आदि और भी बहुत से गांव प्रभावित हुए थे। इस बाढ़ से इन गांवों के लोगों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी थीं, सारे घर तबाह हो गये थे लेकिन उस समय की सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय केन्द्र सरकार से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो राहत राशि आयी थी उसको उस समय की सरकार ने वाजिब हकदारों तक नहीं पहुंचाया और अफसरों की मिलीभगत से तत्कालीन मंत्री ने उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। वे लोग आज भी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। **(इस समय सभापतित्वों की सूची के एक सदस्य श्री रामपाल माजरा चेयर पर पदासीन हुए)** चेयरमैन जी, उस समय बाढ़ राशि के डिस्ट्रीब्यूशन में जो धांधलेबाजी हुई थी उसकी इंक्वायरी करवायी जानी चाहिए और उस समय के संबंधित मंत्री एवं आला अफसरान के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि आगे से कोई भी इस तरह से प्रकृति के प्रकोप के बाद बंटने वाली राशि का दुरुपयोग न कर सके और उस राशि का सही इस्तेमाल हो सके। चेयरमैन जी, उस समय के लोगों को पनिशमैन्ट दी जानी चाहिए। इस दस्तावेज में जिन तीन स्कीम्ज का जिक्र किया गया है उनमें से एक हिसार घग्घर ड्रेन का प्रोजैक्ट भी है। इसी तरह से दूसरी स्कीम इरीगेशन वाटर रिसोर्सिज कंसोलीडेटेड है और तीसरी स्कीम पेयजल की आगमेंटेशन स्कीम है। इन तीनों विभागों के मंत्री एवं ओफिसर्ज यहां पर बैठे होंगे। मेरा उनसे कहना है कि इन तीनों स्कीम्ज का संबंध मेरे हल्के से है। मेरे हल्के नारनौंद का पूर्वी भाग जिसका जिक्र मैंने अभी किया है के काफी गांव उस विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव से अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं। आज भी वहां पर सड़क टूटी पड़ी है। जब मैंने अपने हल्के का इलैक्शन के समय एवं उसके बाद धन्यवादी दौरा किया था तो लोगों को, मां-बहनों को एवं विद्यार्थियों को यह शिकायत थी कि वे अपने गांव से बाहर आ जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं खासकर पूठ्ठी, वाडाला एवं आसपास के गांवों में। जब मैंने इस बारे में जी०एम० और दूसरे अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं हम बस कैसे भेजें ? अब उन सड़कों की कुछ मरम्मत हो चुकी है इसलिए वहां पर बसिज जरूर चलायी जानी चाहिए क्योंकि वे सड़कें बसिज चलने के काबिल हो गयी हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर अधिकारियों को बसिज चलाने के लिए आदेश दिए जाएं। इसके अलावा तो बाढ़ राहत स्कीम घग्घर-हिसार परियोजना शुरू की गयी है उससे वहां के किसानों की जमीन बर्बाद हो गयी है, वे बेघर होते जा रहे हैं इसलिए मेरा

मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यदि आप किसानों को बचाना चाहते हैं तो जो 155 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट इस बारे में प्रौसस में है उसको जल्दी इम्पलीमैन्ट किया जाए। वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इसलिए मेरा उनसे भी कहना है कि अब इसके लिए बहुत कम समय ही रह गया है क्योंकि तीन महीने बाद ही मानसून आ जाएगा। इसलिए इस बारे में जल्दी कार्यवाही की जाए। सर, मेरे हल्के में कई विरोधाभासी समस्याएं हैं। एक तरफ तो मेरे हल्के के पश्चिमी बैल्ट जिसमें मसूदपुर डाटा, गुडाना, खानपुर आदि गांव आते हैं, वे सूखे से जबरदस्त प्रभावित रहते हैं इन गांवों में पेयजल और सिंचाई जल दोनों का लगातार अभाव बना रहता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मसूदपुर लिंक भाखड़ा जो सिस्टम है बरवाला ब्रांच वहां से मसूदपुर लिंक बनिहार ऐक्सटैंशन के नाम से स्कीम मंजूर हुए छह साल का समय बीत चुका है और उस पर एक करोड़ रुपया लग चुका है लेकिन उसमें अभी भी पूरी तरह से पानी नहीं छोड़ा गया है उसमें अभी काफी कमियां हैं, कल्वर्ट आदि बन रहे हैं। वियाना खेड़ा और मसूदपुर के बीच अभी उसकी लाइनिंग होनी है और मैं निवेदन करूंगा कि इस इाइ सीजन से पहले इस काम को सिरे चढ़ाया जाए। कैपेसिटी अथोराइजेशन का काम जल्दी किया जाए ताकि हमारे यहां के लोगों को पानी मिल सके। 10-12 गांव तो सूखे की वजह से बर्बाद होते जा रहे हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं आप पता करवा सकते हैं। हमारे वहां तालाब सूखे पड़े हैं। मैंने एस०ई० से बात की कि मसूदपुर में डब्लू०जे०सी० का जो ऐग्जिसटिंग सिस्टम है उससे हमारे यहां पर पानी दे दो लेकिन वहां पर नहर का बुरा हाल है कहीं गड्डे हैं, कहीं ईंटें उखड़ी पड़ी हैं तो कहीं लाइनिंग गलत हो गई है। मेरा निवेदन है कि आज जो री-बैलिडेशन स्कीम है उसकी रिपेयर वर्ल्ड बैंक स्कीम से जल्दी करवाई जाए ताकि मेरे हल्के के अन्तर्गत जो 15-20 गांव आते हैं उनको पूरी तरह से पानी मिल सके। जहां तक पेयजल की बात है, जो ऑगमैंटेशन स्कीम हैं उनकी भी हालत बहुत ही खराब है। जब मैं अपने धन्यवाद दौरे पर गया था तब मैंने महिलाओं की आंखों में पानी देखा है। थुराला, पेटबाड़, बड़छप्पर, छाड, पुट्टी और मेरे अपने गांव मसूदपुर में पेयजल का विकराल संकट बना हुआ है। अभी भी मैक्सिमम स्कीम प्रौसेस में है बाकी सभी गांवों को भी इसमें कवर किया जाए।

शिक्षा के बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र आया है। मैं बधाई दूंगा कि सरकार ने शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया है लेकिन मेरे हल्के नारनौंद में 70 प्रतिशत स्कूलों में हैडमास्टर नहीं हैं। चेयरमैन सर, यदि स्कूलों में जिम्मेदार आदमी नहीं होगा तो क्या आप समझते हैं कि काम ठीक ढंग से चल पाएगा। जभा दो स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं। टैक्नीकल इंस्टीच्यूटस में टैक्नीकल स्टाफ नहीं है, किस तरह से बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी ? मेरा निवेदन है कि जहां जहां स्टाफ की कमी है वहां वहां स्टाफ को पूरा किया जाए।

सड़कों का बुरा हाल है पीछे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से काफी सड़कों व गलियों के काम शुरू करवाए हैं लेकिन इलैक्शन की वजह से रुक गए हैं मुझे आशा है कि वह काम अब जल्दी ही शुरू करवाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं लोगों को मैडीकल फैसिलिटिज देने की बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० जो काम कर रही हैं उनके बारे में मैं एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात आपको बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उनको भी पता होगा कि बगैर बिल्डिंग के अस्पताल चल रहे हैं क्योंकि कहीं पर बिल्डिंग हैं तो डॉक्टर नहीं हैं और कहीं पर डॉक्टर हैं तो बिल्डिंग नहीं हैं। जो प्राइमरी हैल्थ सैनुटर्ज हैं वहां जाकर आप चैक करें, आज 60 परसैंट जगहों पर डॉक्टर नहीं हैं। जो भी नए डॉक्टर अपॉइन्ट होते हैं वे गांव में जाकर राजी ही नहीं हैं। पता नहीं

[श्री राम भगत]

उन्हें क्या दिक्कत है। पी०एच०सी० और सी०एच०सी० में न डॉक्टर हैं न दवाइयां हैं। यही हाल वैटरनरी हास्पीटल्ज का है। मैं इस महान सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुविधायें शहरी लोगों को दी जाती हैं बड़ी सुविधायें ग्रामीण इलाके के लोगों की दी जाएं चाहे वह पीने के पानी की बात हो चाहे बिजली की बात हो। शहरों में बिजली के कट लगते ही लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस दिशा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम शुरू कर दिया है। युवाओं खासकर विद्यार्थियों, छात्र-छात्राओं के लिए होस्टल और स्पोर्टस् के मामले में जो सरकार ने अच्छा काम किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी एक ज्वलंत समस्या जो आज विद्यार्थियों को प्रभावित कर रही है वह यह है कि हमारे इलाके में जो कालेज हैं उनमें छात्रावास नहीं हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बसों में चढ़कर आना-जाना पड़ता है और बसों में इतनी भीड़ होती है कि कोई विद्यार्थी बस की खिड़की में लटक रहा है तो कोई छत पर बैठे हैं और इस कारण विद्यार्थी आने-जाने में इतने थक जाते हैं कि उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उन कालेजों में छात्रावास का निर्माण किया जाये। मेरे हल्के नारनौंद में 25 किलोमीटर के इलाके में कोई कालेज नहीं है जिसके लिए विद्यार्थियों को दूर-दूर तक पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मेरे हल्के की यह विशेष डिमाण्ड है कि मेरे हल्के नारनौंद में एक को-एजूकेशनल कालेज खोला जाये जिसमें अत्याधुनिक जॉब-ओरियंटिड कोर्सिज हों जैसे कंप्यूटर एजूकेशन, इलैक्ट्रोनिक्स आदि। जहां तक स्पोर्टस की बात है, गांवों के अन्दर स्पोर्टस् के लिए जो सब-सैन्टर और स्टेडियम खोले गये हैं उनमें कोच उपलब्ध नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि वहां पर कोच उपलब्ध कराये जायें। जहां तक महिलाओं के विकास का सवाल है, हालांकि हरिजन महिलाओं के विकास के लिए कन्यादान की स्कीम लागू करने का सरकार ने एक अच्छा काम किया है। इसके साथ ही कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों के परिवारों को राहत प्रदान करने की राशि को बढ़ाया है इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन व्यक्त करता हूं और सरकार इसके लिए मुबारकबाद की पात्र है। गांवों में जो एक विशेष कठिनाई है वह है सुलभ शौचालयों का न होना जिसके कारण महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि शामलात की जमीन को तो पिछली सरकारों ने पता नहीं किस मजबूरी के कारण अपने चहेतों को दे डाला जिस पर नाजायज कब्जे किये हुए हैं और महिलाओं को लैट्रीन जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए जो पास-बुक देने की स्कीम शुरू की थी उसे जल्दी जारी किया जाये क्योंकि पासबुक न होने के कारण किसानों को जो लोन लेना पड़ता है उसमें काफी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। दूसरा किसानों की फसल के लिए जो प्राइस फिक्सेशन का कार्य केन्द्र के मार्फत कराया जाता है उसकी वजह से भी किसानों को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि अनाज मण्डी में उनकी फसल को उचित दाम समय पर नहीं मिल पाता है। मेरे हल्के में आज आलू की फसल का यह हाल है कि किसान कहता है कि उसको उसकी मजदूरी भी पूरी नहीं मिल पा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराने की योजना बनाई जाये जिसके कारण कम भाव के समय किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सके और जब उचित दाम मिल रहा हो तब अपनी फसल को बेच सके ताकि उसे अपनी फसल का उचित दाम मिल सके। मेरे हल्के की जनता ने 30 साल तक सत्तासीन लोगों को उखाड़कर मुझे अपना मेनडेट दिया है ताकि मैं अपने हल्के का सही तौर पर सुधार कर सकूं। मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा बताये गये सुधार के कार्य करवाकर मेरे हल्के की जनता का ध्यान अवश्य रखेगी इसके लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करूंगा। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द, जयभारत।

श्री बलवन्त सिंह (हसनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, कल गवर्नर साहब ने हरियाणा सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष में किये जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहूंगा कि जब भी कोई नई सरकार आती है और वह अच्छे काम करती है तो सभी साथियों को उसकी सराहना करनी चाहिए। हमें लोग चुनकर यहां इसलिए भेजते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अच्छे सुझाव दें, न कि एक दूसरे पर छींटा कसी करें। अगर कोई सरकार गलत काम करती है तो हम उसको बताएं। सभापति महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। एस०वाई०एल० हरियाणा प्रदेश के लोगों की लाइफ लाइन है। कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एस०वाई०एल० नहर का जिक्र किया। मुझे इस बात की खुशी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले श्री चन्द्र शेखर की सरकार के समय एस०वाई०एल० नहर का काम बी०आर०ओ० को दिलवाया था। आदरणीय चौ० ओम प्रकाश चौटाला ने यह तय किया कि जब तक हरियाणा प्रदेश की जनता को पूरा पानी नहीं दिया जाएगा तब तक हरियाणा की जनता का सुधार नहीं हो सकता। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** एस०वाई०एल० नहर हरियाणा प्रदेश के लोगों की लाइफ लाइन है, एस०वाई०एल० नहर का काम पूरा होने से हरियाणा प्रदेश के चप्पे-चप्पे तक पानी पहुंचने का काम होगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौ० ओम प्रकाश चौटाला ने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बहाल करने का किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बन्द करके उन नौजवानों के साथ कितना अन्याय किया जो कि डाक्टर बनने से वंचित रह गए थे। आदरणीय चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने आते ही अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट प्रदान कर दी जो कि एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक ओर जहां नौजवानों के लिए मैडिकल कालेज की ग्रांट बहाल करने का काम किया है वहां दूसरी ओर पिछली सरकार ने पता नहीं किस नीयत से नौजवानों पर नाजायज तरीके से शराब बेचने के आरोप में जो मुकदमें बना दिए थे, इस सरकार ने आते ही उन मुकदमों को वापिस ले लिया। जो गरीब आदमी अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाता लिखाता है और चाहता है कि उसका बेटा जाकर नौकरी करें, उन मुकदमों की वजह से वे नौकरी से वंचित हो गए थे। उन नौजवानों के भविष्य को देखते हुए चौ० ओम प्रकाश चौटाला ने जितने भी ऐसे केस थे वे सारे के सारे वापिस ले लिए। पिछली सरकार के समय नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती थीं। अध्यक्ष महोदय, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने नौजवानों, जिनकी नौकरी लेने की उम्र निकल चुकी थी की आयु सीमा 35 से 40 साल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कर दी है ताकि उन नौजवानों को नौकरी मिल सके और वे हरियाणा की जनता की सेवा कर सकें। स्पीकर सर, जो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे सरकार की तरफ से पैंशन मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चौधरी देवी लाल जी ने 100 रुपये बुढ़ापा पैंशन हरियाणा के उन वृद्धों के मान-सम्मान के लिए शुरू की जिनकी आयु 60 साल से अधिक है। हिंदुस्तान में ऐसी प्रथा पहले नहीं थी चौधरी देवी लाल जी ने ही शुरू की। स्पीकर सर, पिछली सरकारों ने पांच एकड़ भूमि की शर्त रखकर वृद्धों के मान-सम्मान के लिए जो 100 रुपये देवी लाल जी ने देने शुरू किये थे, जमीन के आड़ लगाकर काटने का काम किया था। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश की माताओं और बुजुर्गों को मान-सम्मान देने के लिए वह शर्त ही नहीं बल्कि पैंशन भी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी है। स्पीकर सर, यह बहुत ही सराहनीय काम है। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त चौटाला साहब ने विकलांगों और विधवाओं को दी जाने वाली पैंशन भी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी है। स्पीकर सर, चौटाला साहब ने व्यापारियों द्वारा जो 14.

[श्री बलवन्त सिंह]

15, 5 व 1 नम्बर फार्म भरे जाते थे वे अब समाप्त कर दिये हैं तथा टैक्स भी माफ कर दिया गया है। इस बारे में पिछली सरकारें वायदे करती रही लेकिन उन्होंने अपना यह वायदा नहीं निभाया। चौटाला साहब की सरकार बनते ही उन्होंने अपनी कलम से यह काम सबसे पहले किया। स्पीकर सर, इसी तरह से चौटाला साहब ने उन माताओं को मान-सम्मान देने के लिए जो अपने बच्चे को दूध पिलाकर जवान करती हैं और देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजती हैं, जिन माताओं के सपूत शहीद हो गये, पांच लाख रुपये शहीद के माता-पिता को और पांच लाख रुपये उस शहीद की पत्नी को देने का काम चौटाला साहब ने किया है। जब पिछली सरकार थी तो शहीद के परिवार को पांच लाख रुपये दिलाने का काम भी हमने बड़ी मुश्किल से करवाया था। लेकिन चौटाला साहब की सरकार बनते ही चौटाला साहब ने वह राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी। इस प्रकार से चौटाला साहब ने यह भी बड़ा सराहनीय काम किया है और शहीदों के माता-पिता को पूरा-पूरा मान-सम्मान दिया है। स्पीकर सर, भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है, बहन अपने भाई को राखी बंधन के ऊपर राखी बान्धती है। बहनें अपने भाइयों को कलाई पर धागा बांध कर उनसे वचन लेती हैं कि जब भी हम पर मुसीबत आए तो हमारी रक्षा करने का काम करे और जब बहन या बेटियां उनकी शादी हो जाने पर पति के घर चली जाती हैं तो कभी भी भाइयों से हिस्सा लेकर नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो उस वक्त यह कानून था कि अगर बहन अपने भाइयों से हिस्सा लेने के लिये अदालत में जाकर ब्यान देंगी तो उनका हिस्सा उनको वापिस मिल जाता था लेकिन पीछे चौधरी भजन लाल की सरकार ने यह फैसला लिया और कानून बना दिया कि बहनें अपने भाइयों से हिस्सा नहीं ले सकती और रजिस्ट्री कराने का कानून लागू किया। (शोर) अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने पर उन्होंने चौ० देवी लाल जी के उसी फैसले को मानते हुए दोबारा से यह कानून बना दिया कि जब भी बहनें अपने भाइयों से अपनी जायदाद का हिस्सा लेने की मांग करेंगी तो वे अदालत में जाकर ब्यान दें तो उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी जिनमें चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी थे जो अपनी जान को खतरे में डालकर खम्बों पर चढ़ जाते हैं और अपने जीवन का बलिदान देते हैं, चाहे मैडिकल की नर्सें हैं जो बीमारी के दौरान जनता की सेवा करती हैं, चाहे नगरपालिका के वे कर्मचारी हैं जो अपने सिर पर गन्दगी उठाकर जनता की सेवा करते हैं, पहले वाली सरकार ने उनकी मांगों को न मानते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया था और सेवा मुक्त कर दिया था, इस सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले ही प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी फैली हुई है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उन बिजली कर्मचारियों, मैडिकल नर्सों तथा नगरपालिका कर्मचारियों को बहाल कर दिया जो कि जनता की सेवा करते हैं और उनको वापिस नौकरियां देकर सराहनीय कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर थोड़े ही समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार द्वारा किये गये इतने सारे कामों को देखकर मुझे एक बात याद आती है कि पीछे एक कहावत थी और कहा करते थे तथा हम सुना करते थे कि जो राजा होते थे, वे भेष बदलकर अपने नगरों में घूमा करते थे उसी तरह से केवल हरियाणा प्रदेश में ही हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद पहली दफा ऐसा अवसर आया कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने राजाओं के समय को संभव करते हुए दिखाया और हर विधान सभा क्षेत्र में वे खुद गए और हर जिले के सभी अधिकारी जैसे कि डी०सी०, एस०पी०, एक्सीयनज़, एस०डी०ओज०, तथा बी०डी० एण्ड पी०ओज० आदि सभी वहां मौजूद होते थे। मैं उन सदस्यों को बताना चाहूंगा जो यह कहते हैं कि उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि उनके क्षेत्रों में मुख्य मंत्री महोदय गये हैं, हर विधान सभा क्षेत्रवार वहां पर जो-जो मांगे मुख्य मंत्री महोदय के सामने आई वो सारी रिकार्ड में दर्ज हैं।

यह मैं दावे के साथ कहता हूं। हर गांव में कहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत हो रही हैं तो कहीं नई सड़कें बन रही हैं, कहीं पशु चिकित्सालय बन रहे हैं, तो कहीं गऊ घाट बन रहे हैं और कहीं हैल्थ सैन्टर बन रहे हैं, तो कहीं रिटेनिंग वाल बन रही हैं। इसके अलावा कहीं गलियां बन रही हैं तो कहीं सीमेन्ट की पक्की गलियों का निर्माण किया जा रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिखा दिया कि वे प्रदेश के विकास के लिये जो कह रहे हैं उसे कर के दिखा भी रहे हैं और लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और इतने थोड़े समय में कितने काम कर के दिखाये। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हमें यहां पर अपने सुझाव रखने चाहिएं तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले कामों में कहीं कमी हो तो बताएं लेकिन अच्छे कामों को अच्छा भी बताना चाहिए। मुझे याद है कि सांपला के अन्दर बाजार में एक कंकरीट की सड़क बनाने की बड़ी गुजारिशें मैंने पिछली सरकारों से की थी लेकिन वह सड़क नहीं बन पाई। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने माननीय सदस्यगण जाकर देख सकते हैं कि सांपला के बाजार में डेढ़ से दो फुट मोटी कंकरीट की सड़क बनने लग रही है और यह श्री ओम 12.00 बजे प्रकाश चौटाला जी की देन है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात सर छोटूराम के बारे में याद आती है। चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल जी रहे हों या बंसी लाल जी रहे हों उनके समय में सर छोटू राम के गांव गढ़ी को एक माडर्न गांव बनाने की स्कीम बनाई गई थी। हमने तो इनकी सरकार के कागजों में गढ़ी गांव को माडर्न गांव बनाने की कोई स्कीम नजर नहीं आई। लेकिन भजन लाल जी और बंसी लाल जी सर छोटूराम के नाम का सहारा चुनाव के दौरान अवश्य लेते थे लेकिन उनके गांव की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मेरी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी से प्रार्थना है कि पिछली सरकारों ने तो सर छोटूराम के गांव गढ़ी को माडर्न गांव नहीं बनाया, लेकिन आप अवश्य बनवा दें ताकि लोग कह सकें कि जो काम बंसी लाल जी व भजन लाल जी न कर सके वह काम चौटाला साहब ने कर दिखाया।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि मेरी कान्स्टीच्यूंशी में स्कूलों में जो स्टाफ की कमी है उसको भी सरकार पूरा करने की कोशिश करे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर नहरी पानी की बात भी बहुत बार होती है। मेरे हल्के के जो टेल पर गांव पड़ते थे उन में नहरी पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता था। जब से चौटाला साहब ने सत्ता अपने हाथ में ली है तब से टेल पर पानी पहुंचना शुरु हो चुका है। हसनगढ़ की टेल पर कभी भी पानी डेढ़ फुट से ज्यादा नहीं गया। नीचे से जो रिपोर्ट आती थी उसी को यहां पर सदन में बता दिया जाता था कि फलां टेल पर इतना पानी पहुंच रहा है। इस बारे में चौटाला साहब ने आदेश जारी किए हैं कि अकेले रीडरगेज मैन की ही रिपोर्ट सही नहीं मानी जाएगी बल्कि गांव का सरपंच या नम्बरदार भी रिपोर्ट देगा कि फलां टेल पर पानी कितना पहुंचा है। सरकार ने यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर दिया है उसका पूरा समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री राम किशन (बवानीखेड़ा-अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश तो पंजाब से अलग होकर 1966 में आजाद राज्य बन गया था लेकिन इसी राज्य के बवानीखेड़ा हल्के को जब से हरियाणा अपने अलग अस्तित्व में आया था तब से लेकर आज तक दो पूर्व विधायकों से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। उन्हीं की ही राजनीति इस क्षेत्र में आज तक चलती आ रही थी। अब पहली बार मैं वहां से चुनकर आया हूं, जिस कारण उस क्षेत्र को उन दोनों से मुक्ति मिल पाई है। हमारे एरिया में पीने के पानी

[श्री राम किशन]

की बहुत ही गंभीर समस्या है। पानी की वहां पर इतनी अधिक कमी है कि बवानी खेड़ा के लोग सप्ताह में मुश्किल से एक दिन ही स्नान कर पाते हैं। क्योंकि जो डिग्गियां बनी हैं उनमें पानी नहीं होता, बिना पानी के उनका क्या फायदा है। अगर एक हफ्ता भी उनमें पानी आए तो सूखे के अन्दर तो वह पानी वैसे ही उड़ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले पीने का पानी मिलना चाहिए। हमारे लोगों को सरकारी नौकरियां चाहे मिलें या न मिलें, नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता मिले या न मिले लेकिन हमारे लोगों को पानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्य मन्त्री जी से तथा सरकार से यह विनती है कि हमारे हल्के में पानी की समस्या बहुत ही गम्भीर है इसलिए मेरे हल्के में पानी का उचित प्रबन्ध करवाने की कृपा करें। (विघ्न) हमारे लोगों को तो अगर पीने का पानी मिल जाए तो हम लोग तो सेम के इलाके में भी जाने को तैयार हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी मैम्बरान साहेबान से कहूंगा कि एक नये सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं और वे पहली बार बोल रहे हैं इसलिए उनको बोलने का हौंसला दीजिए।

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक और बात भी यहां पर हाउस में कहना चाहूंगा कि फौजियों और पुलिस के आदमियों को भी सभी पार्टियों को टिकट देने चाहिएं। फौजी लोग बहादुरी से सीमा पर लड़ते हैं उसी प्रकार से पुलिस के लोग भी बहादुरी से लड़ते हैं और लोगों की सेवा करते हैं लेकिन हम लोगों को राजनीति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। क्या फौजी लोग सीमाओं पर केवल गोलियां ही खाने के लिए हैं ? फौजियों और पुलिस के लोगों को इलैक्शन लड़ने के लिए टिकट मिलने चाहिएं। सभी पार्टियों को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा फौजियों तथा पुलिस के लोगों को अपनी पार्टी के टिकट दें। कम से कम 30% टिकट तो हम लोगों को मिलने ही चाहिएं। 30% टिकटों पर तो हमारा हक बनता ही है इसलिए हमें 30% टिकट अवश्य मिलने चाहिएं। इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों के पास इलैक्शन लड़ने के लिए पैसा भी नहीं है इसलिए सभी पार्टियों को चाहिए कि वे इलैक्शन लड़ने के लिए हमें टिकट दें और साथ ही साथ इलैक्शन खर्च के लिए पैसा भी दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक अम्बेदकर भवन बनाया गया था लेकिन उस भवन पर कब्जा किसी और ने कर रखा है इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि उस कब्जे को छुड़ाने में सरकार हमें सहयोग करे। ईशरवाल में हमारा अम्बेदकर भवन है जिस पर * * * ने कब्जा कर रखा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो व्यक्ति हाउस में उपस्थित नहीं है, आप उसका नाम न लें।

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, नाम तो लेना ही पड़ेगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जो मैम्बर हाउस में जवाब नहीं दे सकता उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नाम को कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, नाम को रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि नये लोगों को ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए और दल-बदलुओं को टिकट नहीं मिलने चाहिएं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग भी दल-बदलू हो जाएंगे और हम पर भी उनका असर पड़ जाएगा। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि बवानी खेड़ा की जमीन में कड़वा पानी है और पीने का पानी खराब है इसलिए हमारे इलाके की पानी की प्यास को बुझाना चाहिए और दूसरे हल्कों से पानी लेकर कम से कम दो हफ्ते के लिए पानी

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

जरूर देना चाहिए। सभी पार्टियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारी डिग्गियों और खेतों में पानी मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मुझे गवर्नर साहब के अभिभाषण पर आपने बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री धर्मवीर (तोशाम) : आदरणीय स्पीकर साहब, कल राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा और सत्ता पक्ष ने इसकी बड़ा अच्छा बताया। जब भी कोई नई सरकार आती है तो शुरू शुरू के दिनों में राज्यपाल के अभिभाषण को सारा सदन सराहता है लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा प्रदेश रोता है। इसमें सबसे पहले पानी का जिक्र किया गया है। स्पीकर सर, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। चौटाला साहब की सरकार भी किसानों के एजीटेशन के कारण सत्ता में आई है वर्ना बंसी लाल की सरकार को डेढ़ साल और मिलता। लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद उन सब वातों को सदन के नेता भूल गए। जब भी लोग इनको कहते थे कि आपने ऐसी बात कही थी तो ये कहते थे कि मैंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था। यहां पर एस०वाई०एल० के बारे में भी जिक्र हुआ। इस पानी के अलावा हरियाणा को केवल यमुना से पानी मिलता है। पंजाब प्रदेश हमारा बड़ा भाई है। जब रावी नदी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ था तो उस वक्त कहते थे कि रावी नदी पर डैम पूरा नहीं हुआ है इसलिए पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अब रणजीत डैम पूरा हो चुका है और आज हम सबका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है क्योंकि ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब इकट्ठा हों। जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने अपना हक मांगा है उसी तरह से आज हमें भी संकल्प लेना चाहिए। इस बात के लिए हम और प्रदेश की जनता कई सालों से लड़ाई लड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर कई सरकारें बनी। हमें यह सोचना चाहिए कि रावी के पानी को हरियाणा में कैसे लाएं। हर सरकार यह कह देती है कि अर्थ बर्क हमने पूरा किया लेकिन वह कब पूरा हुआ उस बारे में हर आदमी जानता है। हां, बंद जरूर 1988 में हुआ था। तब से लेकर आज तक उस पर न मिट्टी का काम हुआ है न कंकरीट का काम हुआ है। यह बड़े ही शर्म की बात है। हमारे प्रदेश का अरबों रुपया उस पर लग गया और वह अब बर्बाद हो रहा है। पानी के आज बहुत बुरे हालात हैं। आधे से ज्यादा प्रदेश में पानी खेतों के लिए तो दूर की बात पीने के लिए भी नहीं है। दक्षिणी हरियाणा, भिवानी जिला का 60 प्रतिशत हिस्सा जिसमें बवानी खेड़ा, तोशाम भी आता है आधे से ज्यादा जिला ऐसा है जहां नीचे का पानी खारा है। जैसा कि राम किशन जी बता रहे थे हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है। सिरसा जैसे जिले में 15 दिन पानी चलता है लेकिन हमारे जिले में 3 दिन ही पानी चलता है जो दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं होगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे भी कुछ गांव हैं जैसे सडंबा गांव है जो सबसे पीछे है आप अगर वहां पर जाकर देखेंगे तो लोगों की पब्लिक हैल्थ से एक ही डिमाण्ड है कि हमारे जोहड़ में पानी डाल दो ताकि हम पानी पी लें। यह सरकार एक तरफ तो 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति देने की बात कहती है लेकिन वहां पर दो दिन में एक लीटर पानी प्रति व्यक्ति भी नहीं मिलता है। वहां तो पीने के पानी की ही डिमाण्ड की जाती है। (विघ्न) जहां पर पानी एक महीने में तीन दिन ही आए और टेल पर भी पूरा न जाए तो वहां पर लोग क्या करेंगे। आज हमारे जो जुई और सिवानी फीडर या जितने भी इन फीडर के सिस्टमज हैं सारे के सारे लिफ्ट कैनाल सिस्टम हैं। उनकी आज ऐसी कंडीशन है कि उनकी एफिसिएंशी घटकर 50 प्रतिशत तक चली गई है। वहां पर मोटरें भी नहीं बदली जाती हैं अगर बदल भी जाती हैं तो बिजली चली जाती है जिसकी वजह से जो पानी आना होता है वह नहीं आता है। कहीं कहीं तो 6-6 महीने पानी जाता है। आप भारीकस और छपार जोगिया जैसे गांवों में जाकर देखें जो दूसरे गांवों में जाकर पानी लाते हैं और यह सरकार कहती है कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का प्रबन्ध कर दिया है और सत्ता पक्ष वाले इस अभिभाषण पर बहुत खुश नजर आते हैं। भाखड़ा नहर से जो पानी आता है तो जब तक पक्ष, विपक्ष और भारत सरकार एक होकर रावी का

[श्री धर्मवीर]

पानी हमें न दिलवाये तब तक मेरी प्रार्थना है कि मौजूदा पानी के बंटवारे के सिस्टम को ठीक किया जाए। सिरसा के क्षेत्रफल में तो पानी एक महीने में 15 से लेकर 21 दिन चले और हमारे इलाके में महीने में तीन दिन चले तो यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह पानी का बंटवारा ठीक करें। यमुना नदी का बहाव इन दिनों सबसे कम यानी लगभग दो हजार क्यूसिक से कम हो जाता है। इतना पानी तो 6 जिलों में दिया जाए और आठ हजार क्यूसिक पानी केवल डेढ़ जिले में दिया जाए तो क्या यह ठीक बात है ? अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड से कुछ पैसा हरियाणा प्रदेश में कैनाल और माईनर्ज के लिए आया था लेकिन सरकार बदलने के बाद यह काम अधूरा पड़ा है। मेरी गुजारिश है कि जिन माईनर्ज के लिए यह पैसा आया था उनको पूरा किया जाए ताकि पीने का पानी मिल सके। इस तरह के कुछ माईनर्ज जैसे सागवण माईनर, सिवाड़ा माईनर हैं इनको पूरा किया जाना चाहिए। पानी न मिलने के कारण बहुत सा रकबा खाली पड़ा है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें पूरा पानी दिलवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात को ऐग्जामिन करने के लिए एक तहल कंसलटैन्सी कमेटी बनायी गयी थी। इस कमेटी को केवल यह पता करना था कि पानी का सोर्स कैसे बढ़ाया जाए लेकिन उस पर भी सरकार ने पांच करोड़ रुपये खा लिए परन्तु आज तक भी उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आयी। पांच करोड़ रुपयों से तो जो खराब पम्प हाउसिज थे उनको भी सुधारा जा सकता था। इसलिए हमारा कहना है कि ऐसे पैसे को सरकार को बचाना चाहिए क्योंकि आज प्रदेश के आर्थिक हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं और हर बार केवल कर्ज लेकर काम करने से प्रदेश का भला नहीं होगा। सारा हाउस आज इस बात से चिंतित है। हमें कर्ज लेने के बजाए अपने रिसोर्सिज पैदा करने चाहिएं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं होगा। हमने तो यह भी सुना है कि मार्किटिंग बोर्ड जैसे बोर्ड को जिसका बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये के आसपास का है, को भी लोन लेने की जरूरत पड़ रही है कि कैसे सड़कों की मुरम्मत की जाए। अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में हर सरकार नारा देती है कि हम बिजली देंगे लेकिन आज बिजली की हालत इतनी बुरी है कि खाने के समय में गांवों में देहात में बिजली नहीं आती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि हम किसानों को बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं जबकि सरकार को यह 2.5 रुपये के हिसाब से मिलती है। चौधरी देवी लाल का एक नारा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। वास्तव में उनका नारा सही था और हममें से भी काफी आदमी उन्हीं की देन हैं लेकिन देवी लाल जी के नारे को इम्पलीमैन्ट करने के लिए उनके जैसा बड़ा दिल भी होना चाहिए न कि छोटा दिल। उनके नारे को अगर हमें इम्पलीमैंट करना है तो हमें वैसे ही काम करने चाहिएं। नेहरू जी ने गोबिन्द सागर के ऊपर एक हाईडल प्रोजेक्ट लगवाया था। इस प्रोजैक्ट से जो बिजली बनती है उस पर केवल बीस पैसे के हिसाब से खर्चा आता है जबकि हम किसानों को पचास पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को बीस पैसे यूनिट के हिसाब से ही बिजली दें। इसी तरह से पानी की चोरी भी एक बहुत गंभीर समस्या है जहां से मेन कैनाल चलती है उस इलाके में पानी की चोरी बहुत होती है जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता। पिछले सालों में सरकार ने मेन चैनल में आउटलैट्स दे दिए जिनमें पानी नहीं पहुंचता था मेन कैनाल में कोई मोगा नहीं होना चाहिए। जहां भी मोगे हैं वहां 20-30 फुट के लम्बे पाइप लगें ताकि मोरी को न तोड़ सकें। कुछ साल पहले बालू रेत के इलाके के लिए स्प्रिंकलर सैट्स खरीदे गए थे। 1-1 स्प्रिंकलर सैट्स के तहत 300 एकड़ में पानी लगाया जाता था। करोड़ों रुपये की लागत से यह सैट्स खरीदे गए थे उस योजना को लागू किया जाए ताकि कम पानी से ज्यादा इरीगेशन हो। दो-दो एकड़ के तालाब बनाए जाएं ताकि थोड़े पानी में ज्यादा सिंचाई हो सके। मार्किटिंग बोर्ड जिसका काम है कि किसान की फसल को कैसे

बढ़ाया जाए लेकिन मार्किटिंग बोर्ड शहरों के विकास के लिए पैसा खर्च कर रहा है। जितनी अनाज मंडी बनी, वे सभी बेकार पड़ी हैं। आप किसी भी गांव में जाकर देखें मार्किटिंग बोर्ड का सारा पैसा सड़कें बनाने पर खर्च हो जाता है। हरियाणा प्रदेश में मौजूदा सरकार किसानों की सरकार मानी जाती है लेकिन खाद के भाव बढ़े हैं मेरी प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार ने जो खाद का रेट बढ़ाया है उसकी हरियाणा सरकार अपने पास से भरपाई करके किसानों को सबसिडी दे। हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है फिर भी नकली बीज बेचे जाते हैं उन पर पूरा सोच विचार करना चाहिए। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा मार्किटिंग बोर्ड का फर्ज बनता है कि जब भी कपास जैसी फसल पर कीड़ा लगता है तो ग्लाइडर के माध्यम से मुफ्त किसान की कपास की फसल को बचाया जा सके। नकली दवाइयां होने के कारण कपास का कीड़ा किसान से नहीं मर पाता।

अध्यक्ष महोदय, 29 म्यूनिसिपल कमेटियां तोड़ दी गई हैं सरकार ने यह फैसला कैसे लिया यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन उन 29 कमेटियों के पास जो भी स्टाफ था खासकर सफाई कर्मचारियों का स्टाफ-दूसरी कमेटियां उनको ले नहीं पाएंगी दूसरी बात यह है कि इन कमेटियों को तोड़ने के बाद वहां सफाई कौन करेगा ? पंचायतों के पास फंड नहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस बात पर विचार जरूर करे। उन कमेटियों की बजाय जब पंचायत होंगी तब सफाई कैसे होगी ? बाढ़मुक्त का नारा नयी सरकार ने दिया है लेकिन बाढ़मुक्त के साथ-साथ मेरा एक छोटा सा सुझाव है हमारे बालूरेत के इलाके में जुई नहर और उसके साथ साथ लगते गांवों में सीपेज का काम इसलिए होता है कि बिजली चली जाती है और पम्प हाउस काम नहीं करते हैं और इसीलिए वह सारा इलाका सेम का बना हुआ है। खासकर उस इलाके में एम०आई०टी०सी० ट्यूबवैल के माध्यम से पानी को नहरों में डालें ताकि सिंचाई ठीक से हो सके और समय से बिजाई की जा सके। इसके अलावा बिजली बोर्ड ने जो सिंगल फेस की मोटरें डाली हुई थी मेरी प्रार्थना है कि उन सिंगल फेस की मोटरों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि थोड़े बिजली खर्च में उन पर सिंचाई की जा सके। पिछली बार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए योजना लागू की थी लेकिन उस बागवानी के लिए जितने ट्यूबवैल्ज का कनैक्शन दिया गया उनका खर्च पांच रुपये प्रति यूनिट के आसपास है। यह सरकार किसानों की हितैषी कहलाने वाली सरकार है इसलिए एग्रीकल्चर सैक्टर में जितना खर्चा किसानों को ट्यूबवैल्ज लगवाने के लिए दिया जाता है उतना ही खर्चा बागवानी क्षेत्र में भी दिया जाना चाहिए। ट्यूबवैल्ज के कनेक्शंज हमारे इलाके में थोड़े से ज्यादा देने चाहिये क्योंकि वहां पर इनकी डिमाण्ड ज्यादा है। सीवरेज सिस्टम पर तोशाम हल्के में 70 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन थोड़ा सा काम बकाया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि थोड़ा सा पैसा और देकर उस काम को पूरा किया जाये। नहीं तो जो सरकार का पैसा लगा है वह बर्बाद हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में डिवैल्पमैंट ब्लॉक्स की 1350 के करीब लिस्ट बनाई थी जिनमें से 60 के करीब विकास खण्ड हरियाणा प्रदेश में भी बनते थे जिनके लिए एक करोड़ रुपया प्रति ब्लाक भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस स्कीम के तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का कार्यक्रम था लेकिन सरकार द्वारा उस पैसे को लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर ठेकेदार और दूसरे एजेंटों के माध्यम से काम करवाया जाता है और बेरोजगार युवकों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस पैसे को खण्ड स्तर के मुख्यालय पर दिया जाये ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम किया जा सके। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सरकार द्वारा एक सर्वे कराया गया था उस सर्वे के अनुसार गरीब लोगों को पीला कार्ड देने की योजना थी लेकिन मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो धनाढ्य लोग हैं उनको भी पीला कार्ड जारी किया गया है और उससे वे लोग मिलियन कुवे ट्यूबवैल्ज के कनेक्शन लेते हैं और बाद में उन्हें ठेके पर देते हैं ऐसा एक केस चुनाव

[श्री धर्मवीर]

के दौरान मेरे हल्के में मुझे देखने को मिला। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सर्वे को दोबारा करवाया जाये। जहां तक अस्पताल का मामला है भाई रामभगत जी कोई गलत नहीं कह रहे थे। तोशाम हल्के में अस्पतालों के लिए 50 डाक्टरों की पोस्ट्स हैं परन्तु अस्पतालों में केवल 2-4 डाक्टर ही उपलब्ध होंगे। चुनाव के दौरान मुझे एक अस्पताल में जाने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि अस्पताल के रजिस्टर में एक भी मरीज का नाम दर्ज नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अस्पतालों के लिए बजट में ज्यादा पैसे देने की व्यवस्था करें ताकि गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकें। अमीर आदमी तो कहीं भी अपना इलाज करवा लेते हैं परन्तु गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह प्राइवेट डाक्टरों की फीस अदा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी की बात को आगे चलाने के लिए जो सरकार ने बुढ़ापा पैंशन और विकलांगों की पैंशन को दुगना किया है उसमें कुल दस लाख पात्र आदमी बताये हैं जिन्हें हर महीने 200/- रुपये पैंशन के तौर पर मिलेंगे परन्तु इसके लिए पूरे साल का 163 करोड़ रुपया रखा गया है परन्तु दस लाख लोगों के लिए तो पूरे साल का 250 करोड़ रुपये के लगभग बजट बनता है इसलिए वित्त मंत्री महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये नहीं तो यह स्कीम बीच में ही बन्द करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए जहां प्राइमरी शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है उसको बढ़ाकर कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक करना चाहिए क्योंकि मेरे हल्के में मिडल स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए अलग से कालेज खोले जायें। अगर सरकार मेरे हल्के में लड़कियों के कालेज खोलने के लिए कोई ग्रान्ट मंजूर करती है तो हम बड़े से बड़े लोगों से मिलकर कालेज के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं। आजकल बैड एलीमैंट ज्यादा हैं इसलिए लड़कियों के लिए स्कूलों और कालेजों में अलग से रोडवेज बस व्यवस्था करवाएं तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे आखिरी प्रार्थना है कि हमारा तोशाम का सब डिवीजन तोड़ दिया गया है उसको दोबारा बनवाने के लिए मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि (शोर) जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको ये सही नजर से देखें और ऐसा न सोचें कि फलां भजन लाल जी की पार्टी का है, फलां बंसी लाल जी की पार्टी का है। ये अच्छा काम करेंगे तो लोग इनको सराहेंगे। ये तबादला नीति में भी थोड़ा परिवर्तन करें। मेवात के किसी आदमी को पंचकूला, सिरसा भेजने से सरकार का भी नुकसान है और कर्मचारी का भी नुकसान है। जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। 10वीं विधान सभा का गठन हुआ है इसलिए इस विधान सभा में जो हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, सर्वप्रथम मैं इन सबका हृदय से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। आओ मिलकर हम सभी सदस्यगण चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पद पर हों इस सदन का एक-एक क्षण हरियाणा की समस्याओं का समाधान करने में लगाएं। सभी सदस्यगण गम्भीरता से अपने-अपने पद की गरिमा को निभाएं चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष का भी रचनात्मक रोल होता है। जहां विपक्ष रचनात्मक रोल नहीं निभाता है वहां सत्ता पक्ष भी मर्यादा से बाहर जा सकता है। समस्त हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि आधे विधान सभा क्षेत्रों में पहली बार इलैक्ट्रोनिक मशीनों द्वारा मतदान प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस किया गया है। फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़, फरीदाबाद और मेवला महाराजपुर तीनों क्षेत्रों में

इलैक्ट्रोनिक मशीनों द्वारा मतदान हुआ है। वहां विशेषकर ग्रामीण महिलाओं ने रूचि दिखाई और पहले से ज्यादा संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसके लिए समस्त हरियाणा प्रदेश के चपड़ासी से लेकर मुख्य सचिव तक सभी बधाई के पात्र हैं। पहली बार हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए जबकि दूसरे प्रदेशों में जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश में हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कई-कई हत्याएं हो रही हैं, कई बसें लूटी गई हैं, रेलगाड़ियां रोकी जा रही हैं। इस शांतिपूर्ण मतदान के लिए आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार और सारा प्रशासन बधाई का पात्र है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी हरियाणा की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। राज्यपाल के अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। यह अभिभाषण भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को दर्शाता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो हम सबको मिलकर और अपने पूर्ण दायित्व को निभाते हुए चर्चा और मंथन करने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व-प्रथम यह बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का निर्माण नवम्बर, 1966 को हुआ था तब से लेकर आज तक हरियाणा की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से एक प्रश्न करती रही है, चाहे सरकार चौटाला साहब की हो, भजन लाल जी की रही हो या बंसी लाल जी की रही हो। हर हरयाणवी यही कहता है कि हमारा कैसा प्रदेश है जिसकी न तो अलग से राजधानी है, न अलग से हाईकोर्ट है, न अलग से सचिवालय हो। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस०वाई०एल० के पानी की बात है इसमें मैं समझता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार है और वे मुख्य मंत्री के साथ-साथ अपनी पार्टी के आला-कमांड भी हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हालात होते हैं कि मुख्य मंत्री कहता है कि हाई-कमान ने ना कर दी इसलिए यह कार्य नहीं हो सका और मुख्य मंत्री के सामने इस तरह की परेशानियां आ जाती है। लेकिन चौटाला साहब अपनी पार्टी के हाई-कमान भी हैं इसलिए इनके सामने इस तरह की समस्या नहीं आयेगी और दिल्ली की सरकार से इनको कोई समस्या नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता ने चौटाला साहब को मेनडेट भी क्लीयर दिया है, इनके अपनी ही पार्टी के 46 विधायक हैं। मैं विशेष तौर से चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी से निवेदन करूंगा कि एस०वाई०एल० के पानी के मुद्दे पर वे राजनीति से ऊपर उठकर, वोट बैंक का ख्याल न रखते हुए, चौटाला साहब को पूरा साथ दें ताकि काफी वर्षों से हरियाणा की जनता के सामने चली आ रही पानी की समस्या समाप्त हो सके। स्पीकर सर, हरियाणा और पंजाब दोनों भाई-भाई हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। बंटवारे में कभी-कभी थोड़ी बहुत कमीपेशी रह जाती है। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि पंजाब दूसरा देश है। इन दोनों प्रदेशों में हिंदुस्तान-पाकिस्तान जैसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं दोबारा से चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी से निवेदन करूंगा कि इन तीन-चार मुद्दों के लिए वे वोट बैंक को ध्यान में न रखकर चौटाला साहब का पूरा-पूरा साथ दें और उनसे इस बारे में बात भी करें। मैं चौटाला साहब से भी अर्ज करना चाहूंगा कि वे इस बारे में प्रधान मंत्री जी से बात करें। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब इन समस्याओं के बारे में मिलकर लड़ने का मन बना लेंगे तभी हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं अन्यथा ये समस्या दूर नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने कुरूक्षेत्र में ओथ-सेरेमनी की इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। सभी विधायक वहां पर गये थे, मैं भी वहां पर गया था। निश्चित रूप से कुरूक्षेत्र हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व की ज्योग्राफी में भी कुरूक्षेत्र सबसे पवित्र स्थान है। यह हम सबके लिए बड़े ही फख्र की बात है कि वहां पर चौटाला साहब ने संस्कृत में अपनी शपथ ली। इसलिए भी चौटाला साहब बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा कि सारा विश्व जानता है कि कुरूक्षेत्र की पवित्र धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिये गीता का उपदेश दिया था। चाहे वह मानव किसी भी देश के किसी भी पहाड़ी, रेगिस्तानी अथवा समुद्री क्षेत्र में क्यों न रहता हो और किसी

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारे स्कूल और कालेजों में गीता सन्देश से संबंधी कोई ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि गीता समस्त मानव जाति के कल्याण का ग्रन्थ है और गीता, उपनिषद्, वेद तथा दूसरे जो भी उच्च ग्रन्थ हैं उन सब का पाठ्यक्रम प्रदेश के स्कूल और कालेजों में रखना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बहन-बेटियां हैं वे इनका अध्ययन करके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गुणों को ग्रहण करते हुए अच्छे संस्कार सीखें। इसलिये इस तरह के पाठ्यक्रम को लागू आप कर सकते हैं इसमें कोई अड़चन भी नहीं है। कल ही राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बाढ़ वगैरह के बारे में जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पहली सरकारों ने भी बाढ़ के बारे में अच्छे प्रयास किये हैं। मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से निवेदन करूंगा कि प्रदेश में हर जिले में बाढ़ का प्रकोप आता है लेकिन हमारे फरीदाबाद जिले में जब बारिश होती है और यमुना के अन्दर पानी जाता है तो हर साल बाढ़ के दौरान वहां के घर काफी प्रभावित होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिला प्रशासन को कड़े आदेश दें कि जिन लोगों को वहां बाढ़ दुष्प्रभावों को भोगना पड़ता है उनसे बचाने के लिये सख्त इंतजाम हों तथा पैसे का भी पूरा प्रबन्ध किया जाए। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में जिक्र किया है कि भ्रष्टाचार, जो राज्य में चारों ओर कैंसर की भांति फैल रहा है और महत्वपूर्ण स्त्रोतों को नष्ट किये जा रहा है, पर काबू पाने के लिये सतर्कता, चातुर्य तथा तत्लीनता से कानून और व्यवस्था की स्थापना का अभूतपूर्व विकास करते हुए क्रान्ति के युग में लाकर हरियाणा को संघ के समस्त राज्यों में आदर्श राज्य बनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है कि कोई भी एक व्यक्ति चाहे वह मुख्यमंत्री के पद पर हो, चाहे प्रधान मंत्री के पद पर हो वह इससे अकेला नहीं लड़ सकता। आज जहां समाज में चारित्रिक और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है वहां भ्रष्टाचार से हर घर प्रभावित हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आम आदमी किसी थाने, तहसील या बिजली के बिल भरने या फिर छोटे-मोटे कामों से दफ्तरों में जाता है तो उनके इस तरह के काम बिना पैसे दिये हो जाने चाहिएं क्योंकि 80 फीसदी तो आम आदमी के ही ये काम होते हैं। वैसे तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो यह समझते हैं कि किसी की भी सरकार हो और कोई भी आफिसर हों हम तो पैसे देकर काम करा लेंगे लेकिन समाज के नीचे के वर्ग के तहसील, थानों के या दूसरे छोटे-छोटे जो सरकारी दफ्तरों में काम होते हैं वह तो बगैर पैसे के हो जाने चाहिए। इस तरह से भ्रष्टाचार को तुरन्त रूप से समाप्त करके स्वच्छ प्रशासन देने की मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा की है। सारा सदन पूर्ण रूप से अवगत है कि पूरे भारत में फरीदाबाद काफी महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। लेकिन आज गुड़गांव और फरीदाबाद की स्थिति जो किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां जमीनें एक्वायर कर ली जाती है और बाहर के लोग आकर औद्योगिक यूनिट लगा लेते हैं लेकिन उन किसानों से कोई हमदर्दी नहीं होती जिनकी जमीन एक्वायर की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि कम से कम इससे आगे तो जमीन कम एक्वायर करे। दिल्ली के साथ लगता एरिया चाहे वह फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है या रोहतक है उसका रहन-सहन ऐसा लगता है कि जैसे वह हरियाणा का हिस्सा नहीं है। उनकी वेशभूषा और खान-पान में पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आया हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि दिल्ली के साथ लगते एरिया में लोगों की जमीन एक्वायर न की जाये। यदि जमीन एक्वायर की जाये तो बहुत ही आवश्यक होने पर एक्वायर की जाये। जमीन एक्वायर होने पर जब वहां पर इण्डिस्ट्रीयल यूनिटस लगते हैं तो वहां पर जिन लोगों की जमीन एक्वायर की जाती है उन लोगों के बच्चों को उन यूनिट्स में

नौकरी मिलनी चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता। वे लोग बिहार, गोरखपुर या केरला से आदमी ले आएंगे लेकिन हमारे लोगों को जिनकी जमीन एक्वायर होती है, नौकरी पर नहीं रखते। इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ऐसी कोई नीति बनाए कि यदि जिन लोगों की जमीन एक्वायर होती है तो वहां पर जो यूनिट्स लगें उनमें जिन लोगों की जमीन ली गई है उनके बच्चों को नौकरी अवश्य मिले। मेरा पुनः निवेदन है कि सरकार इस पर अवश्य विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे से पहले भी कई साथियों ने इस बारे में अपने-अपने सुझाव रखे हैं। जैसे कहा जाता है कि जीवन के लिए हवा और पानी जरूरी है, मैं समझता हूं कि आज के हालात में हवा और पानी के साथ-साथ बिजली का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे कोई व्यक्ति किसी झुग्गी में रह रहा है या एक कमरे के मकान में रह रहा है या बड़े मकान या कोठी में रह रहा है, बिजली सभी के लिए बहुत जरूरी हो गई है। सभी सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से पूरे प्रयास भी किए हैं लेकिन इन प्रयासों में हमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है कि हम अपने लोगों को 24 घंटे बिजली दे सकें। सरकार से निवेदन है कि लोगों की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए सभी को 24 घंटे बिजली दिए जाने का प्रबन्ध करे। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एन०टी०पी०सी० गैस पर आधारित प्लांट है। जब इस प्लांट को लगाने की बात आई थी तो उस वक्त वहां के लोगों को कहा गया था कि इस प्लांट से जो बिजली पैदा होगी उसमें से इस एरिया को पूरी बिजली मिलेगी। मेरे हल्के के साथ कृष्णपाल गुर्जर साहब का एरिया लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जमीन एक्वायर हुई थी तो उस वक्त यह कहा गया था कि फरीदाबाद के लोगों को इस प्लांट के लगने से पूरी बिजली मिलेगी। वहां पर उत्पादन शुरु हो चुका है लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया कि उस एरिया को पूरी बिजली मिल सके। वहां पर जो बिजली पैदा हो रही है वह सारी की सारी सेन्ट्रल पूल में चली जाती है जिस कारण वहां पैदा हुई बिजली उस क्षेत्र को मिलने की बजाये दूसरे क्षेत्रों को मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पूरी बिजली न मिलने के कारण लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है। खास कर जिन लोगों ने ट्यूबवैल्ज लगा रखे हैं उनमें तो बहुत बड़ी बेचैनी है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हो सकता है कि लोग अपनी इस मांग के लिए सड़कों पर न उतर आएं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोचे और इस समस्या का समाधान करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल जी ने बिजली के नेटवर्क को काफी प्राथमिकता दी थी। बंसी लाल जी के वक्त करोड़ों रुपये नए ट्रांस्फारमर्ज और बिजली उत्पादन बढाने पर खर्च किए गए थे। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के बल्लबगढ़ में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि मेरे हल्के के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार किया गया। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे हल्के में ज्यादा पैसे देकर वहां पर ट्रांसमिशन और स्ट्रैथंन का काम सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सिंचाई के बारे में भी प्राथमिकता दी है। निश्चित रूप से हमारा हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे एक साथी ने पहले चर्चा की है कि कहीं पर पानी की अधिक मात्रा है तो कहीं पर पानी की बहुत किल्लत है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि कहीं पर तो नहरी पानी इतना अधिक है कि वहां पर 5-5 फुट के नीचे पानी है जिस तरह से सेम की भी समस्या बनी हुई है और कहीं-कहीं पर पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

में लाना चाहूंगा कि अहीरवाल क्षेत्र जिसमें महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, रिवाड़ी, फरीदाबाद आदि क्षेत्र आते हैं वहां पर पानी की बहुत भारी कमी है। वहां के लोग पानी के लिए तरसते हैं। फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स अधिक होने के कारण पानी की काफी कमी है। मैं एक बात और नोटिस में लाना चाहूंगा कि जिन गांवों में पहले मीठा पानी था उन गांवों का पानी भी अब खराब हो चुका है। इस बारे में वहां पर एक सर्वे की रिपोर्ट भी है। वहां पर पीने के पानी के सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं उनमें पीने के पानी का सिस्टम पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि नई-नई बीमारियों का प्रकोप वहां पर फैलना शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब सभी लोगों के प्रयास से एस०वाई०एल० का पानी आएगा तो टोटल फरीदाबाद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ वगैरा जिलों को निश्चित रूप से पूरा पानी मिलेगा और हम सभी के लिए वह दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। गन्ना वगैरह का मूल्य बढ़ाने के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ ही मैं विशेष रूप से इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि कृषि की जमीन धीरे-धीरे कम होती जा रही है और परिवार बढ़ रहे हैं इसलिए किसान की आमदनी कम होती जा रही है इसलिए हमें नये-नये और मॉडर्न सिस्टम्ज़ को एडॉप्ट करना चाहिए और लोगों को ऐसी तकनीक उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। नई फसल, फूल और पौधे लगाने के लिए लोगों को बताना चाहिए जिससे उनको मार्किट में बेच कर उनको सोर्स आफ इन्कम बनाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दूसरे अभी रोहतक बल्लभगढ़ दुग्ध संयन्त्र के बारे में कहा गया है, इसमें भी काफी सुधार की गुंजाईश है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय की ग्रान्ट बहाल करने के लिए धन्यवाद करता हूं। महाराज अग्रसेन के नाम पर जो चिकित्सा महाविद्यालय है वह अग्रवाल समुदाय के कारण से नहीं है। वास्तव में पहले क्या होता था कि इस प्रकार के जो संस्थान थे वे महापुरुषों के नाम पर ही चला करते थे। कई बार यह समझ लिया जाता है कि महाराजा अग्रसेन का नाम होने से यह महाविद्यालय अग्रवालों का है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के आधुनिक काल में चिकित्सा शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। इससे पहले अस्पताल, स्कूल और कॉलेज वगैरह सेठ लोग ही चलाया करते थे और कुछ राशि दान वगैरह से इकट्ठी होती थी। इस कॉलेज की जो ग्रान्ट बहाल की गई है उसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। यह चिकित्सा महाविद्यालय केवल अग्रसेन महाराज के नाम पर ही नहीं बना हुआ है बल्कि यह सभी के लिए है। आज यह एक राष्ट्रीय चिन्तन का प्रश्न है और इससे देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। एक-एक रुपया इकट्ठा करके कोष स्थापित किया गया था और इस कॉलेज की ग्रान्ट बहाल करने के कारण यह सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक हमारा हरियाणा लगता है इसलिए हम कोई ऐसा सिस्टम डिवैल्प कर सकते हैं जिससे किसान की पैदावार को मुल्क से बाहर भेजा जा सके। यूरोप के कई कण्ट्रीज़ में ऐसा सिस्टम है कि वहां के फूल या दूसरे प्रोडक्शन्ज़ बाई ऐयर दूसरी जगहों पर ले जाई जाती हैं लेकिन हमारे यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली ऐयरपोर्ट से हरियाणा का प्रोडक्शन ले कर नौ-दस घण्टे में विमान इंगलैंड या पैरिस में लैण्ड कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई योजना सरकार को अवश्य बनानी चाहिए इससे हरियाणा के किसान का प्रोडक्शन बाहर भेजा जा सकता है और किसान को अधिक फायदा मिल सकता है। मैं समझता हूं कि इस के बारे में सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी और नया सिस्टम डिवैल्प करेगी। इसके साथ ही पशुपालन बहुत ही अच्छा आय का साधन है। सारे देश में

हरियाणा में अच्छी गाय और भैंसें हैं। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हर गांव के अन्दर पशु डिस्पैंसरीज़ जरूर खोलनी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक किसान हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छी भैंस 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं आती है, लेकिन उनमें ऐसी बीमारी होती है जिसका कई दफा उनका उपचार नहीं होता है और पशु मर जाता है। आज पशुओं को नई नई बीमारी होती है। सर, कम से कम हरियाणा में लेटस्ट टैक्नीक की चिकित्सा होनी चाहिए और लेटस्ट सुविधा के चिकित्सालय होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो कारगिल युद्ध की बात की है यह समस्त हरियाणावासियों के लिए गौरव की बात है। जब भी कारगिल युद्ध की बात आती है तो उस वक्त कौन सा हरियाणवी है जिसको इसके लिए गौरव नहीं होता है। जहां तक आर्मड फोर्सिज की बात है, हरियाणा उसमें पहला प्रदेश है। वैसे भी हरियाणा की भूमि को वीरों की भूमि कहा गया है यह बहुत ही गौरव की बात है। चाहे 1962 की लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ 3-3 युद्ध हुए हों या कारगिल का युद्ध हो, यह बहुत ही फख्र की बात है कि हरियाणा का जवान मातृ भूमि की रक्षा के लिए लड़ा है। एक भी जवान भागा नहीं है वह या तो शहीद हुआ है या उसने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। कारगिल की लड़ाई में 18 हजार फीट ऊंची चोटी पर हमारे 114 जवान मारे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम 1962 की लड़ाई की किताब पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि उस वक्त आर्मी की कॉमिनिकेशन टूट गई थी और उनको कह दिया गया था कि भाग जाओ। लेकिन हमारे ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने कहा था कि नहीं हम भागेंगे नहीं। उन्होंने एक नया इतिहास रचा था और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इस प्रदेश के लोग कर्मठ निष्ठा और प्रतिभाशाली हैं। आदरणीय चौटाला साहब ने शहीद के परिवार वालों को जो 10 लाख की राशि और परिवार के सदस्य को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है इसके लिए वे और इनकी सरकार बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, आज अंग्रेजी के अखबार में एक बहुत बड़ा एडिटोरियल है वह बहुत ही खेद की बात है। आज का युग आपा-धापी के साथ पैसे से नापा जाता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत भारी संख्या में सेना के आफिसर और जवान इस्तीफा देकर लौट रहे हैं और जबकि आर्मड फोर्सिज में हजारों पद पहले से ही खाली पड़े हुए हैं। आज लोग सोचते हैं कि फौज में जाएंगे तो 3000 ही मिलेगा इतना तो रेहड़ी लगा कर ही कमा लिया जाएगा। आज अगर नौजवान देश पर मर मिटने के लिए नहीं गया तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर सोचने की और गौर करने की जरूरत है। यह सब क्यों है इसको 13.00 बजे दूर करना चाहिए। फौज में हर कोई आदमी नहीं लड़ सकता। जो मार्शल रेस का आदमी है वहीं जाकर वहां पर मरता है इसलिए इस बात को सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, अब आप वाइन्ड-अप करें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा। सर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें हर जिले के अंदर वार मैमोरियल स्मैट्री खोलने चाहिएं ताकि गांवों के लोग वहां पर आकर देखें। पहले मुझे विधान सभा की एक कमेटी के साथ दूसरे प्रदेशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमने वहां पर देखा था कि जो दूसरे प्रदेशों की राजधानियां हैं उनमें भी वार मैमोरियल स्मैट्री होती हैं अगर हमारे यहां भी थे हर जिले में खोल दी जाएं तो यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। जो भी हरियाणा के जवान या अधिकारी शहीद हुए हैं उनके फोटो या उनके लड़ते हुए के चित्र वहां पर होने चाहिएं। आज तो कारगिल युद्ध की पूरी फिल्म दिखायी जाती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे ज्यादा

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

अच्छा इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और कोई नहीं हो सकता। जब लोग इन स्मैट्रीज़ में आकर अपने शहीदों को देखेंगे तो उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और फिर वे राष्ट्र पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरणा ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस सदन के पुराने साथी हैं इसलिए आप भी कमेटीज़ के साथ बाहर गए होंगे। जब हम उस समय कोहिमा में गए थे तो हमने वहां की वार मैमोरियल स्मैट्री में देखा और पढ़ा कि जो शहीदों के नाम वहां पर थे उनमें सबसे ज्यादा नाम हमारे हरियाणा और पंजाब के ही थे। इनको पढ़कर हम सभी एम०एल०एज० बहुत खुश हुए थे इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह से इतिहास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में भी अभिभाषण में जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले के गांव में एक महिलाओं का सरकारी कालेज खोला जाना चाहिए क्योंकि आज हमारी बहन बेटियों को इसकी बड़ी भारी दिक्कत है उन्हें बीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनके जाने के लिए बसिज की सुविधा भी नहीं है। जो वहां पर थ्री व्हीलर चलते हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। हर आदमी के पास तो कार या स्कूटर नहीं हैं। समाज का आधा भाग साईकिल या ट्रैक्टर से चलता है इसलिए हर जिले में, गांव में महिला कालेज विद होस्टल फैसेलिटीज खोलने चाहिएं ताकि हमारी बहन बेटियों का भला हो सके। इसी तरह से खेलकूद के बारे में भी हमारे भाई गोपी चन्द ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं जोकि हम सभी के लिए गौरव की बात है। हर जिले स्तर पर स्टेडियम वगैरह का निर्माण होना चाहिए। इसी तरह से मैं परिवहन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। यह ठीक है कि पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने ही यह निर्णय दिलवाया था कि ट्रांसपोर्ट का प्राईवेटाइजेशन होना चाहिए लेकिन कई बार अच्छी स्कीम्ज भी फेल हो जाती है। लोग उसे समझ नहीं पाते। आज हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो अच्छी बस सेवा से जुड़ा हुआ हो। पहले गांवों के बच्चों ने जो लोन वगैरह लेकर बसिज चलायी थीं वे सफल नहीं रहीं। 80 परसैंट के करीब वे बसिज बैंकों के हाथों में खड़ी हैं क्योंकि बैंकों ने उनको फाईनेंस दिया था और जो गांवों में थ्री व्हीलर चलते हैं उनकी बहुत बुरी हालत है जिसकी वजह से लोग ऐक्सीडैंट्स में मरते हैं इसलिए आज आम आदमी यही चाहता है कि पहले की ही तरह सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की बसिज चलायी जानी चाहिएं। आज गांव के लोगों को आने जाने के लिए बिल्कुल भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है यह पूर्ण रूप से किसी के भी राज में नहीं कहा जा सकता कि फलां मुख्यमंत्री के समय में राम राज रहा है। क्राइम होते हैं लेकिन प्रशासन का यह दायित्व है कि कानून तोड़ने वालों को हथकड़ी लगाकर न्यायलय में पहुंचाया जाए। लेकिन यह बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि ला एण्ड आर्डर में जो धीरे-धीरे गिरावट आ रही है हम सभी के लिए यह चिंता का विषय है विशेष कर ऐसे जिले जैसे फरीदाबाद है एक तरफ दिल्ली लगती है दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश या राजस्थान लगते हैं वहां का प्रशासन जब उन पर प्रैशर डालता है तो वहां से भागकर वे हरियाणा में फरीदाबाद या गुड़गांव में आ जाते हैं और हीनियस क्राइम ऑपरेट करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां हमें थानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, फोर्स बढ़ानी चाहिए Our Police should be equipped with latest communication system. जैसे जीप है, 30 साल पुरानी जीप यदि किसी थानेदार को दी गई है तो वह क्राइम करने वाले को कैसे पकड़ सकता है और आजकल तो जो लोग क्राइम करते हैं उनके पास मोबाइल भी होते हैं। इस प्रकार जो दिल्ली के नजदीक के जिले हैं उनमें पैसा खर्च करके पूर्ण रूप से पुलिस सिस्टम को स्ट्रैंथन करना चाहिए। थाने बना दिए जाते हैं आखिरकार जवान भी तो ह्यूमैन बीइंग है यदि आप किसी जवान से 15-20 घंटे ड्यूटी लेते हो

और उसके पास रहने के लिए व परिवार को रखने के लिए क्वार्टर भी नहीं हैं जो कि उसकी मूलभूत आवश्यकता है तो वह कैसे ठीक ढंग से काम कर सकेगा ? स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रशासन के अंदर जो एक बड़ी कमी है वह एकाउंटेबिलिटी की है। बसें पलट जाती हैं या 50 लाख की लागत से सड़क बनाई जाती है और वह नाली के ओवरफलो से अगले दिन भर जाती है तो कह दिया जाता है कि अधिकारियों ने गलत कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां निर्माण कार्य पर पैसा खर्च होता है वहां अगर कोई कमी होती है तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए आटोमैटिकली जिस आदमी की गलती की वजह से ऐसा होता है उसको सजा मिलनी चाहिए बजाय इसके कह दिया जाता है कि ट्रांसफर कर रहे हैं। बिजली की तारें कई जगह 15-15 फुट तक नीचे आ जाती हैं जिससे बस ऐक्सीडैंट हो जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। ऐसे में जो अधिकारी वहां से गुजरते हैं उनको यह सब देखना चाहिए और यदि वे नहीं देखते हैं तो ऐसे अधिकारियों को ऑटोमैटिकली सजा होनी चाहिए। दूसरे, मेरे हल्के में एक बड़ा प्रैस्टीजियस प्रोजैक्ट है। मुख्य मंत्री जी को पता है कि वहां यमुना का ब्रिज बनाने का काम शुरू किया है। यह प्रोजैक्ट मोहना में है, वहां 24 घंटे काम चलता था। मेरे चुनाव हारने के बाद वहां किसी ने सुध नहीं ली। जो लोग बना रहे हैं उन्होंने कहा कि यदि हमें सरकार की तरफ से सहयोग हो तो यह काम जल्दी हो सकता है। मैं तो इस बार इंडिपैंडेंट जीतकर आया हूं और मैं 36 बिरादरियों का प्रत्याशी था उसमें मैंने कहा हुआ है कि इस आने वाले दिसंबर तक इस पुल को पूरा करा देंगे और मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि वहां 24 घंटे उसी स्पीड पर काम होना चाहिए क्योंकि दस हजार आदमी रोजाना वहां से आते जाते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण यहां दिया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अजय सिंह (रेवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बात ठीक है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रदेश की जनता ने मेनडेट दिया है। लेकिन जहां तक दक्षिणी हरियाणा का सवाल है वहां पर 19 में से 12 स्थानों पर विपक्षी पार्टी के सदस्य चुनकर आये हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से आज तक दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है इसमें चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे शिक्षा का मामला हो और इसके लिए सरकार को चिन्तन करना पड़ेगा। इस अभिभाषण में लड़कियों को 5100/- रुपये देने की बात कही गई है। इसके बारे में मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि इस बारे में जो गरीबी रेखा का सर्वे हुआ है उसको अगर दोबारा करवाया जायेगा तो पता चलेगा कि काफी परिवार इस योजना से वंचित रह गये हैं उन योग्य परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस अभिभाषण में अग्रोहा मैडीकल कालेज की ग्रान्ट बहाल करने का जिक्र किया गया है। इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के के मीरपुर गांव में रीजनल केन्द्र था जिसकी आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने रखी थी और उसके निर्माण पर सरकार ने लगभग एक करोड़ रुपया लगाया था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने उस रीजनल सैन्टर को बन्द करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि इस रीजनल सैन्टर को शीघ्र चालू किया जाये। सरकार ने हर जिले में डाईट सैन्टर खोले हैं लेकिन हमारे इलाके में न तो कोई डाईट सैन्टर है, न कोई गवर्नमैंट कालेज है, न कोई मैडीकल कालेज है, न कोई इंजीनियरिंग कालेज है। वहां पर एक पोलिटैकनिक कालेज की आधारशिला रखी गई थी लेकिन पिछली सरकार ने वहां होट मिक्स प्लांट लगा

[श्री अजय सिंह]

दिया और बीच में उसका काम रोक दिया। जब इस सरकार का पिछले सात महीनों में शासन रहा तब मुख्यमंत्री जी ने हमारे इलाके के लोगों को आश्वासन दिया था कि रिजनल सैन्टर को एक हफ्ते के अन्दर दोबारा खोल देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे बजट में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा अभिभाषण में वीर सैनिकों के परिवारों को राहत देने की बात कही है। हमारे इलाके के सबसे ज्यादा वीर सैनिक शहीद हुए हैं। आपने शहीदों के परिवारों को दस लाख रुपये देने की बात कही है। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि मेरे इलाके में डबाल गांव में एक सूबेदार सिंहराम 13 कुमाऊं रेजीमेंट का 1962 की लड़ाई में शहीद हुआ था। इसके अलावा 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई में भाग लेते हुए अनेक जवानों ने शहादत दी थी लेकिन उनके परिवार के लोगों को आज तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो वीर सैनिक अब से पहले भी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को भी राहत प्रदान करने का काम यह सरकार करे क्योंकि 13 कुमाऊं बटालियन रेजीमेंट के 114 जवान हमारे इलाके के शहीद हुए थे। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। जहां तक म्यूनिसिपल कमेटीज को एबोलिश करने का सवाल है। सरकार ने 29 म्यूनिसिपल कमेटीज को एबोलिश किया है। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि लोग न तो म्यूनिसिपल कमेटीज और न ही पंचायतों के चुनावों में भाग ले पाये और न ही लोकल बॉडीज के चुनावों में भाग ले पाये हैं। इसलिए सरकार को इस बारे में पुनः विचार करना चाहिये। इसके साथ सरकार ने इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट लागू करने के बारे में आपने अभिभाषण में जिक्र किया कि सरकार इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सबसे अहम मामला है। इराडी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कावेरी नदी के पानी के बटवारे के बारे में वहां की जो रिपोर्ट है, वह लागू हो सकती है और इससे पहले जो बंसी लाल की सरकार थी उस समय बी०जे०पी० भी केन्द्र में थी और आज भी वही हालात हैं। इस सरकार का बी०जे०पी० के साथ गठबन्धन सही है या गलत है ये तो इनको ही पता है। अगर इनका बी०जे०पी० के साथ गठबन्धन सही है तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० के बारे में इराडी कमीशन की जो अन्तिरम रिपोर्ट है उस पर बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए जैसे कावेरी की अन्तिरम रिपोर्ट लागू करवाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थे और उन स्टेट्स के मुख्य मंत्री उस कमेटी के मैम्बर हैं। उसी प्रकार एस०वाई०एल० के बारे में एक कमेटी बनाकर इराडी कमीशन की रिपोर्ट यहां पर लागू करवा दें तो यह दक्षिणी हरियाणा के लोगों पर इस सरकार का बहुत बड़ा उपकार होगा क्योंकि राबी-व्यास का पानी सही मायने में हमारे ही इलाके का है। 1.8 एम०ए०एफ० पानी में से 80 प्रतिशत पानी सिरसा और हिसार दोनों जिले ही ले रहे हैं जो कि हमारा हिस्सा पड़ता है। इसके बारे में हर विधान सभा में यह बात उठी है कि दक्षिणी हरियाणा के हिस्से का पानी दक्षिणी हरियाणा के लोगों को ही मिलना चाहिए लेकिन आज तक उस पानी का समुचित बटवारा नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने भाषण में बताया कि इन्होंने पंजाब को 10.84 करोड़ रु० भाखड़ा मेन लाइन जो कि पंजाब में आती है की गाद निकालने, उसकी सफाई और उसके ठीक रख-रखाव के लिए दिए थे, क्या सरकार बताएगी कि उसके बारे में क्या हुआ कि वह गाद निकाली गई है या नहीं निकाली गई तथा वह पैसा कहां गया और उसके बारे में क्या पंजाब से कोई बातचीत हुई ? उसी प्रकार से भाखड़ा मेन लाइन की कैपेसिटी 10700 क्यूसिक से घटकर 9100 क्यूसिक हो गई है। आगमैंटेशन कैनाल की कैपेसिटी 4500 क्यूसिक से घटकर 2800 क्यूसिक रह गई है जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा दक्षिणी हरियाणा भुगत रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कई

इलाकों में सेम आ रहा है और मुख्यमंत्री महोदय ने अभी बताया कि वे सिरसा में बाढ़ की रोकथाम के उपाय कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है। कई-कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं जैसा कि थोड़ी देर पहले बहन अनीता जी ने बताया कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को 3-3 रुपये के हिसाब से पानी का मटका मिलता है। इसी प्रकार से मेरे हल्के की निखरी डिस्ट्रीब्यूटरी, एक्सटैंशन जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की एक्सटैंशन के लिए नाबार्ड द्वारा बाकायदा बड़ी-बड़ी स्कीमज़ बनाई हुई हैं, लेकिन जानबूझकर इस मामले को लटकाया जा रहा है ताकि उन डिस्ट्रीब्यूटरी से ज्यादा पानी लेने की कैपेसिटी न बढ़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके की बालावास डिस्ट्रीब्यूटरी, लाधूवास डिस्ट्रीब्यूटरी और रालियावास डिस्ट्रीब्यूटरी हैं जिनकी टेल्स पर आज तक पानी नहीं पहुंचा है। इसके अलावा लिफ्ट इरीगेशन कैनालस की कैरिंग कैपेसिटी मात्र 25 फीसदी रह गई है। जहां पर मोटर जल गई है उनकी कोई रिपेयर नहीं करता है, उनके बाशर्ज, बाल्वस, पम्प सैट्स की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनका पानी कैसे आगे पहुंचे। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके लिए न तो बर्ल्ड बैंक से कोई पैसा लिया गया है और न ही नाबार्ड से कोई बात की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खासकर मेरे इलाके की लिफ्ट इरीगेशन कैनालस के रख-रखाव की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं यह बात इसलिए विस्तार से कह रहा हूं कि यदि इन लिफ्ट इरीगेशन कैनालस का रख-रखाव ठीक हो जाएगा तो वहां के लोगों में आत्म-विश्वास पैदा होगा। इसके अलावा मसानी ब्रांच का मुद्दा है, राजस्थान में जब ज्यादा बरसात होती है तो वे पानी हमारे यहां छोड़ देते हैं जिसके कारण हमारे यहां फल्ड आ जाता है और वह पानी झज्जर तक नुकसान करता है, उसके बारे में हमारी सरकार को राजस्थान सरकार से बात करनी चाहिए कि वे फालतू पानी को रोकने का कोई सिस्टम बनाएं जिससे हमारे यहां के किसानों का सिंचाई का काम ठीक प्रकार से हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं पावर सैक्टर के बारे में कहना चाहूंगा कि अखबारों में आया है कि बर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रु० का लोन आया है और उसकी पहली किश्त 240 करोड़ रु० की मंजूर हुई है लेकिन उस 240 करोड़ रु० में से मात्र 130 करोड़ रुपये ही पहुंचे हैं, क्या सरकार इस बारे में इस सदन को बताएगी कि उनको आज तक कितना लोन मिला है और उस लोन से रिफोर्मिंग और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? इसी प्रकार मैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में कहना चाहूंगा, यहां पर आप लोग कहते हैं कि हमने इतना बिजली का उत्पादन कर दिया लेकिन गांव के घरों में बल्ब नहीं जलते हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि 11 के०वी० की ट्रांसमिशन लाइनों की हालत बहुत ही दयनीय है। जब 11 के०वी० लाइनों का ट्रांसमिशन पर लोड आता है तो ट्रांसफारमर्स जल जाते हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम सरकार का मेन काम है, खासकर 11 के०वी० की लाइनें हैं जो गांव में जाती हैं उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर गांव और ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन एक ही ट्रांस्फार्मर से कर रखे हैं। जिसकी वजह से वहां पर कुछ ऐसे ऐसे गांव व कालोनिज हैं जहां पर लैम्प से तो पढ़ा जा सकता है लेकिन बल्ब की लाईट से नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि बल्ब की रोशनी लैम्प की रोशनी से भी कम है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारी सरकार जो पांच महीने पहले बनी और बीच में लोक सभा के चुनाव भी आये। इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। फिर भी कैप्टन साहब ट्रांस्फार्मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इकट्ठे कनैक्शंज हमारी सरकार ने किये हैं, पहले अलग-अलग थे ? अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब भी मंत्री रहे हैं उस वक्त इन्होंने ये कनैक्शन अलग-अलग क्यों नहीं किये ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब 1991 से 1996 तक मंत्री रहे और

[श्री धीरपाल सिंह]

चौधरी भजन लाल जी उस समय मुख्य मंत्री थे और इन्हीं के नेतृत्व में विधान सभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त कैप्टन साहब दक्षिणी हरियाणा से एक मात्र कांग्रेस के विधायक बने थे।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दक्षिणी हरियाणा से ही चुनकर आया था।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, राव नरेन्द्र सिंह जी भी दक्षिणी हरियाणा से ही चुनकर आये थे। सिर्फ दो ही विधायक उस समय दक्षिणी हरियाणा से कांग्रेस के बने थे। इससे पता लगता है कि उस वक्त इनकी सरकार ने अध्यक्ष महोदय क्या कार्य किये थे। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने बिजली की सप्लाई सुधारने की कोशिश की है।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो अपने हल्के की समस्याएं बता रहा हूं और यह सरकार का दायित्व है कि वे उन्हें सुने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि हमारा इलाका ट्यूबवैल वेर्सड इलाका है। वहां पर नहरों का जाल नहीं है। हमारे वहां के लाखों ट्यूबवैल कनैक्शन पैंडिंग हैं। उनकी दैस्टिंग रिपोर्ट भी हो चुकी है और इस बारे में सरकार ने भी कहा था कि हम वे कनैक्शन रिलीज कर देंगे लेकिन अब तक नहीं किए हैं। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब से जानना चाहूंगा कि वे कनैक्शन किसने काटे थे ?

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे कनैक्शन पिछली सरकार के समय में काटे गये थे। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : गोपी चन्द जी, प्लीज आप बैठिये। कैप्टन साहब, वे कनैक्शन 1991 में आपकी सरकार के समय काटे गये थे।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है। आप रिकार्ड मंगवाकर कर देख सकते हैं कि वे कनैक्शन पिछली सरकार के समय में कटे थे या हमारी सरकार ने काटे थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान सिंगल विंडो सर्विस की तरफ दिलाना चाहूंगा। एच०एस०आई०डी०सी० ने मानेसर और बावल के अंदर कम्पलैक्स बनाये हैं जबकि धारूहेड़ा में बहुत पुराने कंपलैक्स बने हुए हैं। वे तो आज तक भी डवैल्प नहीं हुए हैं। जब पुराने कंपलैक्स ही डवैल्प नहीं हुए हैं तो नये बनाने की क्या जरूरत थी ? वहां पर किसानों की जमीन एक्वायर करके वे कंपलैक्स बनाए गये हैं और किसानों को बेरोजगार कर दिया गया है। इस बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर सिंगल विंडो सर्विस को ठीक तरीके से चलाना है तो पहले, पहले वाले कंपलैक्स को डवैल्प करना चाहिए और फिर दूसरे बनाने चाहिएं। जबकि भिवाड़ी बिल्कुल हमारे साथ ही है। वहां पर बहुत ज्यादा डवैल्पमैंट है। वह कैसे हो गई। जबकि हमारे यहां बिल्कुल भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डवैल्पमैंट न होने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर आज तक भी जो प्लॉट्स दिये गये हैं उनकी रजिस्ट्रीज नहीं हुई हैं। इण्डस्ट्रीज प्लॉटस का भी यही हाल है। वहां पर बहुत पहले सहगल मिल आई थी, उस बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सहगल मिल के पास वहां पर बहुत ज्यादा जमीन है और उसका कुछ पता नहीं है। उसको सरकार को दोबारा से रि-आक्शन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर डवैल्पमैंट न होने का मुख्य कारण यही है कि हमने वहां पर सिंगल विंडो सर्विस

को ठीक तरीके से लागू नहीं किया। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसको ठीक तरीके से लागू करें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अर्बन डवैल्पमैंट में जो मेन दिक्कत आ रही है वह यह है कि धारूहेड़ा के अंदर हुडा के प्लॉट्स पर लोगों ने पोजैशन ही नहीं लिया है। जबकि हुडा ने पोजैशन दिए काफी समय हो गया है। इसके अतिरिक्त चारों तरफ ईललीगल कालोनियां भी बनी हुई हैं। इस बारे में सरकार ने भी कोई पोलिसी नहीं बनाई है। उन कालोनिज में स्लम्ज भी बहुत ज्यादा है इसलिए लोग वहीं पर प्लॉट खरीदते हैं। हुडा को इस बारे में कोई पोलिसी बनानी चाहिए ताकि हुडा के प्लॉट्स की तरफ लोगों का झुकाव हो। इस बारे में मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ऐसे-ऐसे इण्डस्ट्रियल बैल्टस में छोटे-छोटे प्लॉट काटे जाएं ताकि गरीब आदमी उन्हें खरीद सके और किस्तों की सहूलियत भी दी जानी चाहिए।

श्री धीरपाल सिंह : आप इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं या रिहायशी।

श्री अजय सिंह : सर, मैं रिहायशी प्लॉट्स की बात कर रहा हूं। जबकि बराबर में रिवाड़ी इतना अच्छा बना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इललीगल कलोनाइजेशन चल रही है वह प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है। प्रशासन के लोग कलोनाइजर्ज से मिले हुए हैं। गुड़गांव, रिवाड़ी और बड़े टाऊन्ज के अन्दर जो इस तरह की क्लोनाइजेशन है उसके बारे में सरकार कुछ कार्यवाही करे। इसी तरह से मैं लोकल-सैल्फ गवर्नमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। कई ऐसे-ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर सलम पैदा हो रहे हैं। जैसे कि मेरे हल्के के अन्दर ऐसे एरियाज़ हैं जहां न तो सीवरेज की कोई व्यवस्था है और न कोई स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था है। शिव कालौनी, रामसिंहपुरा के अन्दर न तो कोई सीवरेज की व्यवस्था है, न ड्रेनेज की व्यवस्था है और न कोई पानी की व्यवस्था है। इसी तरह रामसिंहपुरा-अजय नगर के अन्दर एक स्कूल है जो सरकारी पैसे से बना हुआ है और वह बिल्डिंग टूटने के कगार पर है। सरकार के जो अधिकारी हैं उनको वहां जाकर देखना चाहिए कि स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है। मैंने सरकार के नोटिस में भी यह बात लाई थी और वहां के डिप्टी कमीशनर के नोटिस में भी यह बात लाई है कि इस तरह की अनसेफ बिल्डिंग्ज़ जो कि गिरने वाली हैं उनके बारे में कुछ कार्यवाही करें लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि महम जैसे कस्बे के अन्दर तो बाई-पास हैं जबकि रिवाड़ी इतना बड़ा टाउन है वहां पर बाई-पास नहीं बनाया गया। झज्जर जैसे शहर में बाई-पास बन गया है जो बाद में जिला बन गया है। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, कलान साहब जो कह रहे हैं मैं उनकी बात में कुछ संशोधन करना चाहूंगा। जब कलान साहब विपक्ष में बैठे थे, मैं भी विपक्ष में बैठा था तो हाउस के नेता चौधरी बंसी लाल थे जिन्होंने बार-बार सदन को गुमराह किया था कि झज्जर में बाई-पास बन रहा है। मैंने वहां पर जाकर मौका देखा तो कोई बाई-पास नहीं मिला। फिर मैंने हाउस में सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि एन०सी०आर० के तहत बाई-पास को बनाया जाएगा फिर मैंने एन०सी०आर० का मामला देखा तो एन०सी०आर० में भी कुछ नहीं मिला। अब कलान साहब पता नहीं कौन से बाई-पास को झज्जर में देख कर आये हैं।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने भाषण में कह रखा है कि झज्जर में बाई-पास का काम चल रहा है। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वो तो आगे की बात है। अब बाई-पास बनेगा। (शोर) जबकि कलान साहब तो अपने भाषण में यह कह गये कि झज्जर में बाई-पास बन गया है।

श्री अजय सिंह : मैंने कहा है कि बन रहा है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप चेयर को संबोधित करके अपनी बात कहें।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो भेदभाव की नीति है उसी का परिणाम है कि उधर आज 18 में से 12 सीटें हमने जीती हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आपके दो मिनट शेष है।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में कह रखा है कि मार्किट बोर्ड फीस का रूरल सैस कम किया गया। इस रूरल सैस के इकट्ठा होने से इनकी सड़कें बनती थीं, जो एक्सीडैंट हुआ करते थे और जिन किसानों के हाथ कट जाया करते थे उनको बाकायदा आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा बकायदा इस सैस में चोरी भी हुआ करती थी। इन्होंने जो रूरल सैस कम कर दिया है उससे अब 1% में भी चोरी तो होगी ही। अभी भाई धर्मबीर कह रहे थे कि क्या कारण है कि मार्किट बोर्ड की पोजिशन खराब है। उसका मुख्य कारण यही है कि इन लोगों ने केवल व्यापारियों और आढ़तियों को फायदा पहुँचाया है। जो किसान है जिसको फायदा होना चाहिए जिसके लिये सड़कें बनती थीं, उस रूरल सैस को कम कर देना सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य श्री धर्मबीर ने एक बात की शंका जाहिर की थी कि मार्किट बोर्ड से शहरों में गलियां और सड़कें बनाने का काम हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से श्री धर्मबीर जी और हाउस के सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के बनने के बाद ही यह फैसला लिया गया कि भविष्य में मार्किट बोर्ड के पैसे से शहरों में गलियों और सड़कों का निर्माण और रख-रखाव नहीं होगा। जब चौधरी भजन लाल 1991 से 1996 तक सदन के नेता थे और जयप्रकाश जी मार्किट बोर्ड के चेयरमैन थे तो करनाल के शहरों में सड़कों के रख-रखाव पर पैसा खर्च हुआ। अध्यक्ष महोदय ऐसी परम्परायें तो इन लोगों ने डाली थीं जबकि हम तो उन परम्पराओं को दुरुस्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह दोपहर बाद होने वाली सिटिंग में कान्टीन्यू करेंगे। Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. today, the 10th March, 2000.

*13.30 P.M. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. today the 10th March, 2000.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

31887—H.V.S.—H.G.P. Chd.